



भारत सरकार / Government of India  
जल शक्ति मंत्रालय / Ministry of JalShakti  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
Department of Water Resources, River Development  
& Ganga Rejuvenation

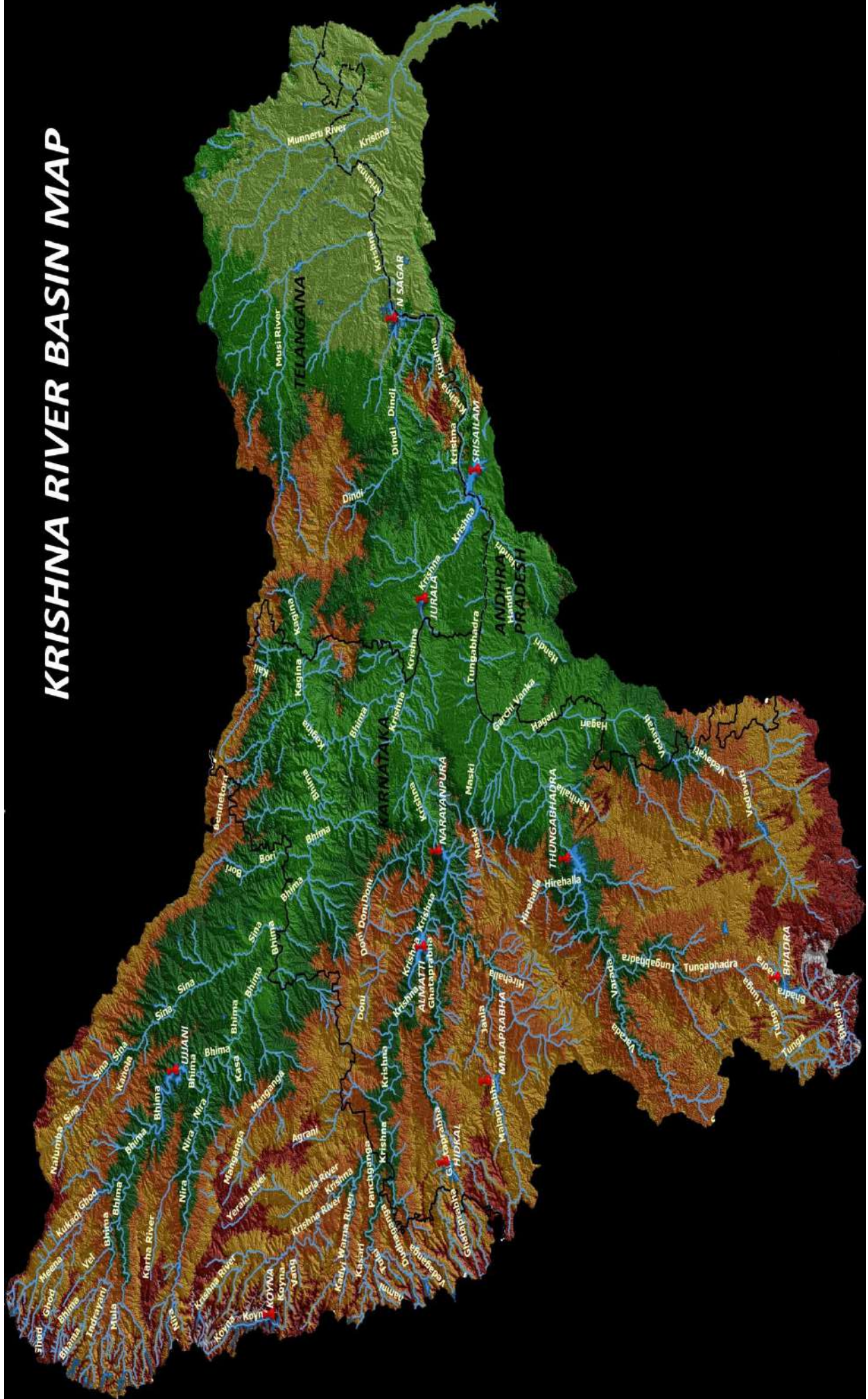


## कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड Krishna River Management Board

वार्षिक प्रतिवेदन  
2021-2022



# KRISHNA RIVER BASIN MAP





सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
Government of India



कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड  
Krishna River Management Board

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
Department of Water Resources, River Development & Ganga  
Rejuvenation

जल शक्ति मंत्रालय  
Ministry of JalShakti

वार्षिक प्रतिवेदन  
2021 - 22





## अध्यक्ष की ओर से

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 प्रस्तुत करने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट कृष्णा नदी बेसिन और वर्ष के दौरान बोर्ड के कार्यों, गतिविधियों और प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन जल संसाधन मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) की अधिसूचना संख्या : 1148, दिनांक : 28-05-2014 और आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का धारा 85 (1), (4) और (5) के अनुसार किया गया है।

केआरएमबी जल शक्ति, आरडी और जीआर मंत्रालय के मार्गदर्शन और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों के समर्थन के तहत एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 (8) के तहत निर्धारित अपने अनिवार्य कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 2842(ई) दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से केआरएमबी के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया। दोनों राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं को सौंपने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। बाद में 14वीं बोर्ड बैठक में समन्वय समिति का नाम बदलकर उप-समिति कर दिया गया और अधिसूचना के प्राथमिकताबद्ध कार्यान्वयन के लिए 15वीं बोर्ड बैठक में उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई।

अंत में, मैं कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों द्वारा कोविड महामारी के बावजूद अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण किए गए असाधारण प्रयासों को स्वीकार करना चाहता हूँ, जिसने बोर्ड को अपने कार्यों को निष्पक्ष और सफलतापूर्वक करने में सक्षम बनाया।

इस वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से संभव हो सका है। मैं इस रिपोर्ट को सामने लाने में योगदान देनेवाले सभी लोगों के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

**(शिव नंदन कुमार)**  
अध्यक्ष, केआरएमबी



## सदस्य सचिव का संदेश

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के दौरान केआरएमबी द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को शामिल करता है।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन 02.06.2014 को केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था। बोर्ड के कार्यों में कृष्णा नदी के उन परियोजनाओं का प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन शामिल है और जिनको समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

DoWR, RD & GR, जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 15.07.2021 को अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड आमतौर पर कृष्णा बेसिन में निर्दिष्ट परियोजनाओं पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। 13वीं, 14वीं और 15वीं कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की बैठकें 9 अगस्त, 2021, 1 सितंबर, 2021 और 12 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गईं। इन बैठकों के दौरान, बोर्ड ने दोनों राज्यों द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं और दोनों राज्यों के बीच जल आपूर्ति विनियमन के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

प्रस्तावित 27 टेलीमेट्री स्टेशनों में से, केआरएमबी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जल लेखांकन और कृष्णा जल के न्यायसंगत बंटवारे के लिए कृष्णा बेसिन के विभिन्न स्थानों पर चरण- I के तहत 18 टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित किए हैं। शेष 9 टेलीमेट्री स्टेशन चरण-II के तहत स्थापित किए जाने हैं।

केआरएमबी ने MoJS, DoWR, RD & GR के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और स्वच्छता पखवाड़ा आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

मैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनके बहुमूल्य सुझावों और मार्गदर्शन के लिए अध्यक्ष, केआरएमबी को अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं इस रिपोर्ट को लाने में उनके प्रयासों के लिए केआरएमबी के अधिकारियों और कर्मचारियों, विशेष रूप से श्री जी. श्रीनिवास राव, कार्यकारी अभियंता, श्रीमती पी. रमा, कार्यकारी अभियंता, श्री पी. रवि चंद्रा, उप कार्यकारी अभियंता और श्रीमती के. सावित्री, सहायक कार्यकारी अभियंता की सराहना करता हूं।

(डी. एम. रायपुरे)  
सदस्य सचिव, केआरएमबी

## वर्ष 2021-2022 की मुख्य विशेषताएँ

- केआरएमबी की 13वीं (आपातकालीन), 14वीं और 15वीं (विशेष) बोर्ड बैठकें क्रमशः 9 अगस्त, 2021, 1 सितंबर, 2021 और 12 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गईं।
- जल वर्ष 2021-22 के दौरान तीन सदस्यीय समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।
- तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, केआरएमबी द्वारा दो (02) जल निकासी आदेश जारी किए गए थे।
- जल वर्ष 2021-22 के दौरान चेन्नई जल आपूर्ति समिति की एक बैठक आयोजित की गई।
- केआरएमबी सचिवालय के कामकाज में केआरएमबी वेबसाइट, LIMBS, RTI, ई-समीक्षा, GeM, ई-प्रोक्योरमेंट, आदि ई-गवर्नेंस गतिविधियों को लागू किया गया।
- भारत सरकार के विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम अर्थात् स्वच्छता पखवाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि का आयोजन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 18.00 करोड़ रुपये का बजट अनुमान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- केआरएमबी का क्षेत्राधिकार DoWR, RD & GR (MoJS) द्वारा राजपत्र S.O. 2842(E) दिनांक 15.07.2021 में अधिसूचित किया गया था।
- श्रीशैलम परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना पर 15 प्रत्यक्ष निर्गम को प्राथमिकता के आधार पर सौंपने पर उप-समिति की अंतरिम सिफारिश को 15वीं बोर्ड बैठक में स्वीकार कर लिया गया।

## विषय सूची

अध्याय संख्या	नाम	पृष्ठ
	अध्यक्ष की ओर से	i
	सदस्य सचिव का संदेश	ii
	वर्ष 2021-2022 की मुख्य विशेषताएँ	iii
1	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अवलोकन	1
2	कृष्णा नदी	4
3	बोर्ड के कार्य	8
4	बोर्ड संगठन	11
5	बोर्ड की बैठकें	14
6	प्रशासनिक मामले	18
7	वित्तीय मामले	20
8	तकनीकी मामले	23
9	संसद प्रश्न, आरटीआई, अति विशिष्ट सन्दर्भ, क्षमता निर्माण और अदालती मामले	32
10	अन्य गतिविधियाँ	35
	अनुलग्नक I (भारत का राजपत्र - APRA 2014 की संख्या 6, 2014)	42
	अनुलग्नक II (राजपत्र अधिसूचना - केआरएमबी गठन)	46
	अनुलग्नक III (ग्यारहवीं अनुसूची)	48
	अनुलग्नक IV (कृष्णा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समिति का गठन)	50
	अनुलग्नक V (18 और 19 जून 2015 की बैठक के कार्यवृत्त)	52
	अनुलग्नक V का परिशिष्ट	56
	अनुलग्नक VI (एपी और टीएस द्वारा नहर / योजना-वार जल निकासी)	59
	अनुलग्नक VII (कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण)	61

## प्रतिवेदन में प्रयुक्त संकेताक्षर

एडीसीपी	ध्वनिक डॉप्लर धरा प्रोफाइलर
ए एम् आर पी	एलिमिनेटि माधव रेड्डी परियोजना
ए पी	आंध्रप्रदेश
एपी जेनको	आंध्रप्रदेश विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड
एपीआर ए 2014	आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
सी इ ए	केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण
सीवीसी	केंद्रीय अन्वेषण आयोग
सी डब्ल्यू सी	केंद्रीय जल आयोग
सी डब्ल्यू ईएस	केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (गुप'ए') सेवा
सीडब्ल्यू पी आर एस	केंद्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान स्टेशन
डी ओ डब्ल्यू आर	जल संसाधन विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
एफ आर एल	पूर्ण जलाशय स्तर
जी ओ आई	भारत सरकार
जी डब्ल्यू डी टी	गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण
एच एन एस एस	हंद्री नीवा सुजल स्रवंति
आई & सी ए डी	सिंचाई और सिंचित क्षेत्र विकास
आई एस आर डब्ल्यू डी ए	अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम
के जी बी ओ	कृष्णा गोदावरी बोर्ड संगठन
के आर एम् बी	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
के डब्ल्यू डी टी	कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण
एम् ओ जे एस	जल शक्ति मंत्रालय
एन आई एच	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
एनआर एस सी	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
एल आई एस	लिफ्ट सिंचाई योजना
एल एम सी	बायीं मुख्य नहर
आर एम सी	दाहिनी मुख्य नहर
एम डी डी एल	न्यूनतम खींचाई स्तर
एम् डब्ल्यू	मेगावाट
एन एस पी	नागार्जुन सागर परियोजना
एन एस एस आर एस पी	नीलम संजीव रेड्डी सागर श्रीसैलम परियोजना
आर डी एस	राजोलिबंडा परिवर्तन योजना
आर डी & जी आर	नदी विकास & गंगा संरक्षण
आर टी आई	सूचना का अधिकार
एस सी ए डी ए	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण

एस एल डी सी पी	साइड लुकिंग डॉप्लर करंट प्रोफाइलर
टी एम सी	हजार मिलियन घन फीट (2831 एच ए एम)
टी एस	तेलंगाना राज्य
टी एस जेनको	तेलंगाना राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड
डब्ल्यू आर डी	जल संसाधन विभाग

## अध्याय -1

# कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अवलोकन

### 1.1 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (के आर एम बी) का संविधान

तत्कालीन आंध्रप्रदेश राज्य को आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों के रूप में विभाजित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को संसद में पारित किया गया था और राष्ट्रपति के आदेशों के तहत कानून एवं न्याय मंत्रालय ने राजपत्र संख्या वर्ष 2014 का. 6 (भाग-2)। दिनांक : 1 मार्च 2014 के माध्यम से इस अधिनियम को प्रकाशित किया गया (अनुलग्नक-1)। इस अधिनियम का भाग IX नव निर्मित राज्यों के जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास से संबंधित है।

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 (भाग IX) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने, जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2014 के माध्यम से, स्वायत्त दर्जे से केंद्र सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन के लिए कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) का गठन किया। एमओडब्ल्यूआर आरडी और जीआर द्वारा जारी किये गये केआरएमबी की अधिसूचना (भाग II – धारा 3) दिनांक 28.05.2014 का राजपत्र कि एक प्रति अनुबंध-II के रूप में रखा गया है।

#### कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (के आर एम बी) की संरचना इस प्रकार है :

(1)	केंद्रीय जल अभियांत्रिकी (ग्रुप 'ए') सेवा से भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर का एक अधिकारी।	अध्यक्ष
(2)	नव निर्मित तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्यों में से दो सदस्य, प्रत्येक रूप से नामित किए जानेवाले, उनमें से एक तकनीकी सदस्य जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे न हो और दूसरा प्रशासनिक सदस्य जो संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा।	सदस्यों
(3)	सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवा का एक विशेषज्ञ।	सदस्य
(4)	केंद्रीय जल अभियांत्रिकी (ग्रुप 'ए') सेवा का एक अधिकारी जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे का न हो।	सदस्य सचिव

बोर्ड ने 2 जून 2014 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात् आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रयोजनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 04-03-2014 की अधिसूचना के माध्यम से नियत दिन अधिसूचित किया गया।

## 1.2 मुख्यालय

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का मुख्यालय नव निर्मित आंध्रप्रदेश राज्य में होना है। हालांकि, बोर्ड का मुख्यालय वर्तमान में हैदराबाद में है और केआरएमबी के मुख्यालय को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।

## 1.3 बोर्ड के कर्मचारी

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 86(1) के अनुसरण में, बोर्ड ने नव निर्मित राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहण हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सदस्य के पद केआरएमबी के लिए सम्मिलित हैं और डीओडब्ल्यूआर, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तैनात किए जाते हैं। सदस्य (विद्युत्) का पद भी संवर्गित है और विद्युत् मंत्रालय द्वारा तैनात किया जाता है।

## 1.4 अर्थ व्यवस्था

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 86(2) के अनुसरण में, आंध्रप्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार हर समय बोर्ड को अपने कार्यों के निर्वहण के लिए आवश्यक सभी खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करेगा और उक्त राज्यों में से प्रत्येक निर्दिष्ट करें कि इस तरह की राशि को संबंधित राज्यों के बीच उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार लाभ के संबंध में कर सकती है।

## 1.5 शीर्ष परिषद्

केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों को पर्यवेक्षण करने के लिए एक शीर्ष परिषद् एपेक्स कौंसिल) का गठन किया।

**शीर्ष परिषद् (एपेक्स कौंसिल) का संगठन निम्न प्रकार है -**

- (a) जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार – अध्यक्ष,
- (b) आंध्रप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री – सदस्य,
- (c) तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री – सदस्य

**शीर्ष परिषद् (एपेक्स कौंसिल) के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं –**

- (i) कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- (ii) कृष्णा और गोदावरी नदी पर आधारित नई परियोजनाएँ, यदि कोई भी हो, उनके निर्माण के प्रस्तावों की योजनाओं को तैयार करना और उनका अनुमोदन करना जिनका मूल्यांकन एवं सिफारिश नदी प्रबंधन बोर्डों एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गयी है।

- (iii) नव निर्मित राज्यों के बीच होनेवाले बातचीत और आपसी समझौते के माध्यम से नदी जल के बँटवारे से उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद का सौहार्द पूर्ण ढंग से समाधान ।
- (iv) किसी भी विवाद जो कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के तहत शामिल नहीं किए उसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित किए जानेवाले ट्रिब्यूनल को समाधान हेतु भेजना ।

## अध्याय -2 कृष्णा नदी

### 2.1 परिचय

कृष्णा बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% है। बेसिन की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई लगभग 701 किमी और 672 किमी है, यह 73°17' से 81°9' पूर्वी देशांतर और 13°10' से 19°22' उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है।

कृष्णा नदी उत्तर में बालाघाट श्रेणी, दक्षिण में पूर्वी घाटों में, पूर्व और पश्चिम में पश्चिमी घाटों से घिरा है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के उत्तर में 1,337 मीटर की ऊंचाई पर महाराष्ट्र के सातारा जिले के जोर गांव के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक नदी की कुल लंबाई 1,400 किमी है।

दाहिनी ओर से जुड़ने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा हैं जबकि बाई ओर से जुड़नेवाली नदियाँ भीमा, मूसी और मुन्नेरु हैं।

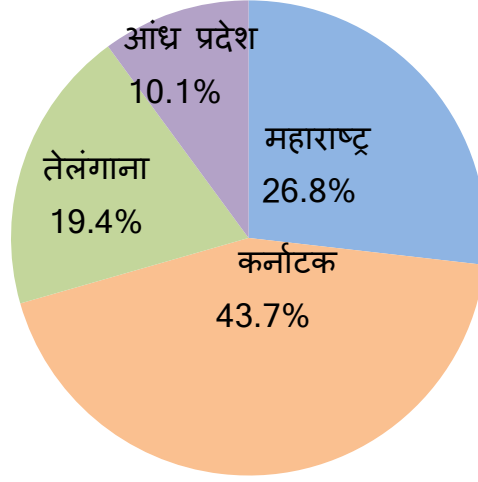
बेसिन का प्रमुख भाग कुल क्षेत्रफल का 75.86% कृषि भूमि से आच्छादित है और बेसिन का 4.07% जल निकायों द्वारा कवर किया गया है।

कृष्णा नदी जल ग्रहण क्षेत्र एवं लंबाई का राज्यवार वितरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका - 2.1

बेसिन स्थित राज्य	लंबाई कि.मी. में	जलग्रहण क्षेत्र वर्ग कि.मी. में
महाराष्ट्र	306	69425
कर्नाटक	483	113271
तेलंगाना	612	50155
आंध्रप्रदेश		26097
<b>कुल</b>	<b>1401</b>	<b>258948</b>

## कृष्णा नदी में बेसिन क्षेत्र का राज्यवार प्रतिशत



### 2.2 प्रमुख सहायक नदियाँ

कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ तालिका - 2.2 में दर्शाई गई हैं।

तालिका - 2.2

क्र.सं	सहायक नदी	लंबाई कि मी (औसतन)
1	कोयना (आर)	119
2	घाटप्रभा (आर)	283
3	मालप्रभा (आर)	306
4	तुंगभद्रा (आर)*	531
5	वेदवती (आर)	391
6	भीमा (एल)*	861
7	मूसी (एल)	267
8	पालेरू (एल)	153
9	मुन्नेरू (एल)	196

\* कृष्णा नदी की दो प्रमुख उप नदियाँ तुंगभद्रा व भीमा स्वयं प्रमुख अंतर्राज्यीय नदियाँ हैं।

### 2.3 उप-बेसिन

बेसिन में जल संसाधनों की योजना एवं विकास के उद्देश्य से कृष्णा नदी बेसिन को निम्नलिखित 12 उप-बेसिनों में विभाजित किया गया है, जैसा कि तालिका-2.3 में दिया गया है।

तालिका - 2.3

क्र.सं.	उप-बेसिन	संख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी में	क्षेत्रफल प्रतिशत में
1	ऊपरी कृष्णा	के 1	17972	7
2	मध्य कृष्णा	के 2	17558	7
3	घाटप्रभा	के 3	8829	3
4	मालप्रभा	के 4	11549	4
5	ऊपरी भीमा	के 5	46066	18
6	निचली भीमा	के 6	24548	10
7	निचली कृष्णा	के 7	36125	14
8	तुंगभद्रा	के 8	47827	19
9	वेदवती	के 9	23590	9
10	मूसी	के 10	11212	4
11	पालेरू	के 11	3263	1
12	मुन्नेरू	के 12	10409	4
<b>Total</b>			<b>258948</b>	<b>100</b>

#### 2.4 आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी

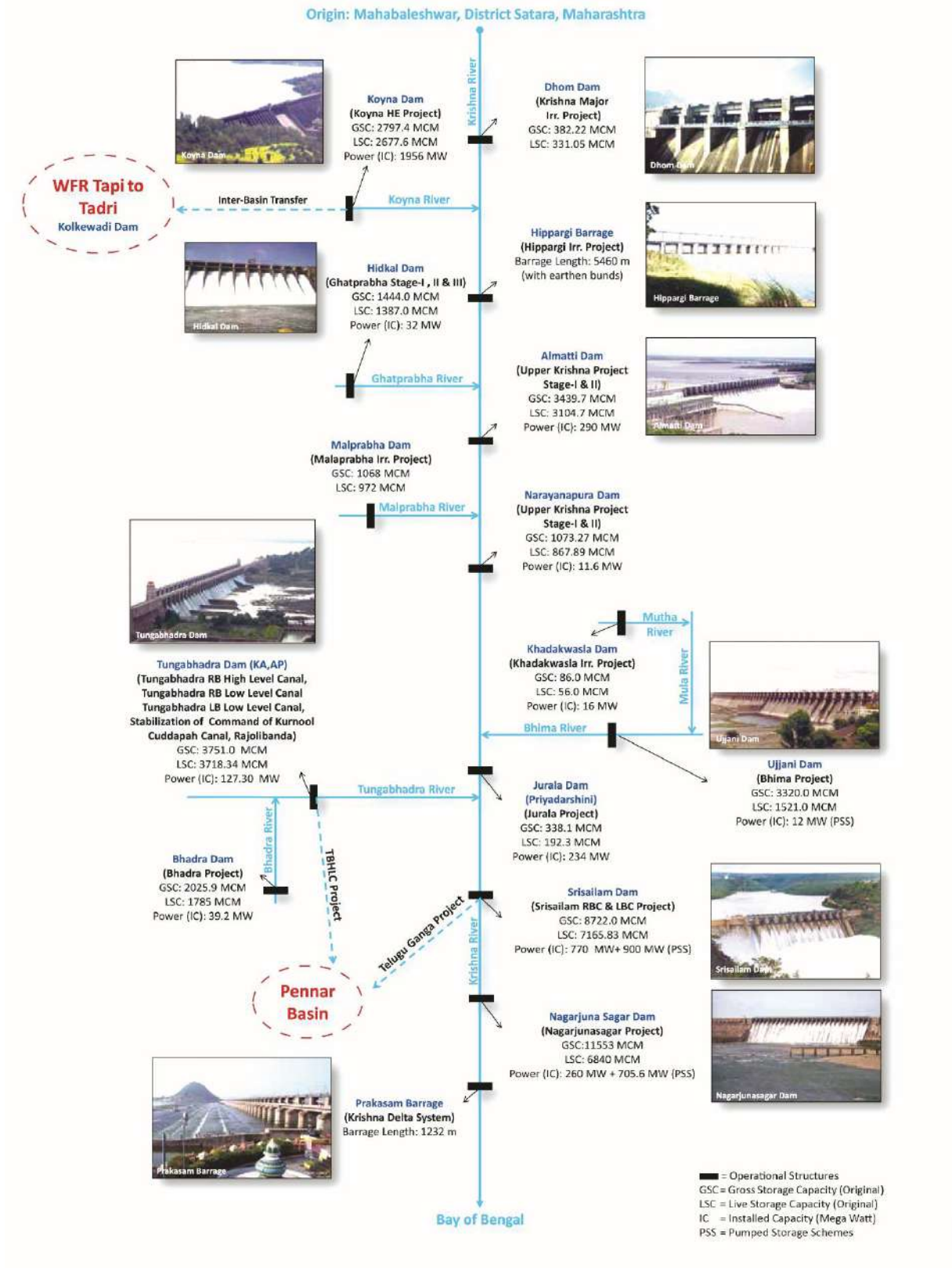
प्रियदर्शिनी जूराला तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बनी सबसे उजान परियोजना है और जो राज्य पुनर्गठन के बाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह परियोजना निचली कृष्णा उप-बेसिन में स्थित है। तुंगभद्रा, वेदवती, मूसी, पालेरू और मुन्नेरू उप-बेसिन आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अंतर्गत आनेवाले कृष्णा नदी के दूसरे उप- बेसिन हैं।

कृष्णा नदी उनके साथ सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, मूसी, पालेरू और मुन्नेरू जो स्वयं में अंतर राज्य नदियाँ हैं, कृष्णा नदी में जुड़नेवाली सहायक नदियों के साथ तेलंगाना और आंध्रप्रदेश दोनों राज्यों में बहती हैं।

नीलम संजीव रेड्डी सागर परियोजना (श्रीशैलम), नागार्जुन सागर परियोजना, डॉ. के.एल. राव पुलिचिंतला परियोजना और प्रकाशम बैराज कृष्णा नदी पर प्रमुख मौजूदा परियोजनाएँ हैं। दो प्रमुख परियोजनाएँ श्रीशैलम और नागार्जुन सागर दोनों आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सेवा करती हैं।

कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बाँध, राजोलीबंडा डायवर्जन स्कीम (आर डी एस) और सुंकेसुला बैराज तीन बड़े परियोजना मौजूद हैं। तुंगभद्रा नदी पर निर्मित तुंगभद्रा बांध, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों राज्यों को पानी उपलब्ध कराता है।

# नदी प्रवाह रेखा अरेख



## अध्याय-3 बोर्ड के कार्य

### 3.1 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के कार्य

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के खंड 85(8) के तहत निर्धारित बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं-

- (अ) निम्नलिखित के संबंध में परियोजनाओं से नव निर्मित राज्यों को पानी की आपूर्ति का विनियमन।
- (i) अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित अधिकरणों द्वारा दिए गए जल आवंटन निर्देश।
  - (ii) वर्तमान आंध्रप्रदेश राज्य या अन्य राज्य या संघ शासित क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किया गया कोई समझौता या व्यवस्था;
- (आ) वर्तमान आंध्रप्रदेश राज्य या अन्य राज्य या संघ शासित क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी समझौते या व्यवस्था के संबंध में बिजली के वितरण के प्रभारी प्राधिकारी को उत्पन्न बिजली की आपूर्ति का विनियमन;
- (इ) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित निर्माणाधीन कार्य या नए कार्यों को राज्य सरकारों द्वारा पूरा करना।
- (ई) कृष्णा नदी पर बननेवाली नई परियोजनाओं के निर्माण के लिए किसी भी प्रस्ताव का मूल्यांकन करना और तकनीकी मंजूरी, इस बात से संतुष्ट होने के बाद देना कि ऐसी परियोजनाएं नियत दिनों से पहले पूरी की जा चुकी या शुरू की गई परियोजनाओं के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरणों के निर्णयों के अनुसार पानी की उपलब्धता को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती हैं; और
- (उ) ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कोई कार्य।

#### 3.1.1 ग्यारहवीं अनुसूची

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की ग्यारहवीं अनुसूची में नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों को नियंत्रित करनेवाले सिद्धांतों को शामिल किया गया है और यह **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

### 3.2 राजपत्र अधिसूचना:

एपीआर अधिनियम, 2014 की धारा 87 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, DoWR, RD & GR (MoJS) ने केआरएमबी के क्षेत्राधिकार को राजपत्र S.O.2842(E) दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया है।

- राजपत्र अधिसूचना के समयबद्ध कार्यान्वयन और संचालन में केआरएमबी कार्यालय और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य सरकारों के संबंधित विभागों / निगमों को सुविधा प्रदान करने के लिए अध्यक्ष, केआरएमबी के अनुमोदन से ओ.एम. दिनांक 02.08.2021 द्वारा एक "समन्वय समिति" का गठन किया गया था। केआरएमबी की समन्वय समिति की पहली बैठक 03.08.2021 को आयोजित की गई और राजपत्र अधिसूचना में विभिन्न खंडों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गई।
- विभिन्न तकनीकी बैठकों के अलावा, कृष्णा जल बंटवारे, बिजली उत्पादन के मुद्दों और केआरएमबी के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना कार्यान्वयन के मुद्दों को सुलझाने के लिए 13वीं (आपातकालीन), 14वीं और 15वीं (विशेष) बोर्ड बैठकें क्रमशः 09.08.2021, 01.09.2021 और 12.10.2021 को आयोजित की गईं।
- केआरएमबी की 14वीं बोर्ड बैठक में, केआरएमबी कार्यालय और दोनों राज्य सरकारों के संबंधित विभागों/निगमों को राजपत्र अधिसूचना के खंडों के समयबद्ध कार्यान्वयन और संचालन की सुविधा के लिए केआरएमबी कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 15.09.2021 के माध्यम से पहले गठित "समन्वय समिति" को "उप-समिति" नाम से पुनर्गठित किया गया।
- उप-समिति की पहली, दूसरी और तीसरी बैठकें क्रमशः 17.09.2021, 30.09.2021 और 10.10.2021 को आयोजित की गईं। इस उप-समिति की अंतरिम रिपोर्ट को इसकी तीसरी बैठक में अंतिम रूप दिया गया है और 12.10.2021 को बोर्ड की 15वीं बैठक में रोडमैप को मंजूरी दी गई थी, जिसमें उप-समिति की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सभी प्राथमिकता वाले श्रीशैलम परियोजना के 7 प्रत्यक्ष आउटलेट घटक और नागार्जुन सागर परियोजना के 8 प्रत्यक्ष आउटलेट घटक केआरएमबी को सौंपने को शामिल करते हुए मंजूरी दी गई थी।
- इसके बाद, आंध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग ने सरकारी आदेश (Ms. संख्या 54) दिनांक 14.10.2021 के माध्यम से और आंध्र प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने सरकारी आदेश (Ms. संख्या 17) दिनांक 14.10.2021 के माध्यम से GoTS द्वारा समान घटकों को सौंपने के

साथ-साथ उनके नियंत्रण में आने वाले घटकों को KRMB को सौंपने के निर्देश जारी किए हैं। तेलंगाना के घटकों को सौंपने के लिए सरकार के आदेशों का अभी भी इंतजार है। इसलिए, केआरएमबी को घटकों का वास्तविक हस्तांतरण अभी तक दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा प्रभावित नहीं किया गया है।

## अध्याय-4 बोर्ड संगठन

### 4.1 संगठन

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) की स्थापना 2 जून, 2014 को आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 (1) के अनुसरण में की गई थी।

### 4.2 बोर्ड सचिवालय

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये गए हैं।

- (i) अध्यक्ष,
- (ii) सदस्य सचिव,
- (iii) सदस्य (विद्युत) और
- (iv) सदस्य

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो बोर्ड के सुचारू कामकाज के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के साथ निहित है। अध्यक्ष को सदस्य सचिव, सदस्य (विद्युत) और सदस्य (बोर्ड सचिवालय में) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवाओं से नियुक्त सदस्य सचिव, बोर्ड के प्रशासन और वित्तीय मामलों के पर्यवेक्षण के प्रभारी हैं। विद्युत मंत्रालय से नियुक्त सदस्य (विद्युत), विद्युत संबंधी मामलों को देखने के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवा से मुख्य अभियंता के स्तर के बोर्ड सचिवालय में सदस्य तकनीकी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में सदस्य सचिव, सदस्य (विद्युत) और सदस्य के अधीन अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता स्तर के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संबद्ध कर्तव्यों और कार्यों को संबंधित इकाइयों के तहत समूहीकृत किया जाता है और प्रत्येक इकाई को विभागों में विभाजित किया जाता है, जिसके प्रमुख कार्यपालक अभियंता, उप निदेशक / निदेशक (वित्त) होते हैं। कार्यपालक अभियंता, उप निदेशक / निदेशक (वित्त) को उप के स्तर के अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाता है। जैसे कार्यपालक अभियंता, सहायक निदेशक, सहायक कार्यपालक अभियंता, अधीक्षक, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और जूनियर सहायक।

सदस्य सचिव, सदस्य और सदस्य (विद्युत) के तहत कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

- (i) सदस्य सचिव के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय इकाई
1. प्रशासन एवं समन्वय विभाग
  2. वित्त विभाग
  3. जल प्रबंधन विभाग
- (ii) सदस्य के अधीन तकनीकी इकाई
1. मूल्यांकन एवं निगरानी विभाग
- (iii) सदस्य (विद्युत) के अधीन विद्युत इकाई

### 4.3 पदधारी

वर्ष 2021-2 के दौरान कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर पदधारियों का विवरण तालिका -4.3 में दिया गया है।

तालिका – 4.3

क्र.सं	पदनाम	नाम	अवधि
1	अध्यक्ष	श्री ए. परमेशम	01-04-2021 से 31-05-2021
		श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर (लिंग अधिकारी)	01-06-2021 से 06-07-2021
		श्री एम. पी. सिंह	07-07-2021 से 31-03-2022
2	सदस्य सचिव	श्री डी.एम. रायपुरे	01-04-2021 से 31-03-2022
3	सदस्य (विद्युत)	श्री एल.बी.मुआनथंग	01-04-2021 से 31-03-2022
4	सदस्य	श्री हरिकेश मीना	01-04-2021 से 31-07-2021
		श्री रवि कुमार पिल्लई	13-09-2021 से 31-03-2022

### 4.4 राज्य सरकारों द्वारा नामित बोर्ड के सदस्य

राज्य सरकारों की ओर से नामित बोर्ड के सदस्यों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

आंध्रप्रदेश सरकार		
1	सदस्य (प्रशासन)	श्री जे श्यामला राव, सचिव, जल संसाधन विभाग 01.04.2021 से 22.02.2022 तक
		श्री शशिभूषण कुमार, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग 23.02.2022 से 31.03.2022 तक
2	सदस्य (तकनीकी)	श्री सी. नारायणा रेड्डी प्रमुख अभियंता (आई), जल संसाधन विभाग
तेलंगाना सरकार		
1	सदस्य (प्रशासन)	श्री डॉ.रजत कुमार, भा.प्र.से तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव, सिंचाई और सीएडी विभाग
2	सदस्य (तकनीकी)	श्री सी. मुरलीधर प्रमुख अभियंता (आई), सिंचाई और सीएडी विभाग

#### 4.5 अन्य अधिकारी/ बोर्ड के कार्यकर्ता

केंद्र सरकार के कर्मियों के अलावा, अधीक्षण अभियंता के स्तर से सहायक कार्यपालक अभियंताओं के स्तर के अन्य इंजीनियरिंग अधिकारी और निदेशक (वित्त) के स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक/अनुसचिवीय अधिकारियों को तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और सीडब्ल्यूसी की सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति / परिवर्तन / ऋण के आधार पर तैनात किया जाता है।

दिनांक : 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में 29 कार्यरत हैं और उनका विवरण निम्न प्रकार है:

भारत सरकार	-- 4
आंध्र प्रदेश सरकार	-- 14
तेलंगाना सरकार	-- 9
सीडब्ल्यूसी (ऋण आधार पर)	-- 1
आंध्र प्रदेश सरकार (डायवर्जन)	-- 1

बोर्ड सचिवालय का संगठन मानचित्र <https://krmb.gov.in/krmb/orgChart> लिंक पर उपलब्ध है

## अध्याय -5 बोर्ड की बैठकें

### 5.1 बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2021-22 के दौरान, तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

क्र.सं	बैठक	तारीख	अध्यक्ष
1	13वीं (आपातकालीन) बोर्ड बैठक हैदराबाद	09.08.2021	म.प्र. सिंह. अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
2	14वीं बोर्ड बैठक हैदराबाद	01.09.2021	म.प्र. सिंह. अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
3	15वीं (विशेष) बोर्ड बैठक, हैदराबाद	12.10.2021	म.प्र. सिंह. अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

#### बोर्ड की तेरहवीं बैठक

- बोर्ड की 13वीं (आपातकालीन) बैठक केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड के क्षेत्राधिकार का अधिसूचना एसओ 2842(ई) दिनांक 15.07.2021 के प्रकाशन के बाद जीआरएमबी के साथ संयुक्त रूप से 09.08.2021 को हैदराबाद में आयोजित की गई थी।
- उपरोक्त अधिसूचना की विभिन्न कार्रवाई योग्य धाराओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

#### बोर्ड की चौदहवीं बैठक

बोर्ड की 14वीं बैठक 01.09.2021 को हैदराबाद में आयोजित की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- कृष्णा बेसिन में जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा की गई।  
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने लघु सिंचाई, गोदावरी के मोड़ के तहत उपयोग पानी और वाष्पीकरण हानि को छोड़कर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए क्रमशः 66:34 के अनुपात में कृष्णा जल के बंटवारे के लिए 2020-21 की कार्य व्यवस्था को चालू वर्ष 2021-22 के लिए भी जारी रखने का निर्णय लिया।
- तेलंगाना द्वारा पानी के अप्रयुक्त हिस्से को अगले जल वर्ष में ले जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई।  
अध्यक्ष, केआरएमबी की राय है कि यदि अप्रयुक्त पानी को किसी एक राज्य के हिस्से को

आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सामान्य जलाशय में संग्रहीत किया जाता है, तो यह अगले वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा सामान्य हिस्से के लिए शुद्ध उपलब्ध भंडारण को कम कर देगा।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, दोनों राज्य प्रत्येक मामले के आधार पर पेयजल आवश्यकता के मुद्दे पर विचार करने और एक-दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

- बांधों की अधिकता के दौरान पानी के उपयोग के मुद्दे पर चर्चा की गई।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, सभी मुख्य स्टेम जलाशयों में अधिशेष होने पर भी दोनों राज्यों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए जारी राशि का हिसाब रखने पर सहमति हुई।

- बाढ़ की अवधि के दौरान जब सभी बांध अधिशेष होते हैं तो दोनों राज्यों द्वारा उपयोग की छूट के मुद्दे पर चर्चा की गई।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि अधिशेष अवधि के दौरान मोड़े गए सभी जल का डेटा दर्ज किया जाना चाहिए और लेखा रखा जाना चाहिए।

- जीआरएमबी की 11वीं बैठक में जीआरएमबी के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से केआरएमबी के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना की कार्रवाई योग्य धाराओं के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई।

### बोर्ड की पंद्रहवीं बैठक

बोर्ड की 15वीं (विशेष) बैठक 12.10.2021 को हैदराबाद में आयोजित की गई।

बोर्ड ने श्रीशैलम और नागार्जुन सागर परियोजनाओं के 15 प्राथमिकता वाले घटकों को शामिल करते हुए केआरएमबी के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना के प्राथमिकता वाले कार्यान्वयन के लिए रोड मैप के संबंध में उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।

### 5.2 तीन सदस्यीय समिति की बैठकें और परिणाम

जल वर्ष 2021-22 के दौरान दोनों राज्यों के प्रमुख अभियंताओं और सदस्य सचिव, केआरएमबी की तीन सदस्यीय समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। जल रिलीज आदेश मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे।

- i) पीने और सिंचाई के पानी की आवश्यकताएँ।
- ii) जलाशयों में भंडारण की स्थिति।
- iii) बिजली का उत्पादन।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि पानी के बंटवारे के लिए राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत समग्र अनुपात का पालन किया गया था।

तीन सदस्यीय समिति की बैठकों की सिफारिशों के अनुसार, जल वर्ष 2021-22 के दौरान

केआरएमबी द्वारा श्रीशैलम और नागार्जुन सागर की सामान्य परियोजनाओं से विभिन्न निर्गम से सिंचाई आवश्यकताओं और हैदराबाद शहर और चेन्नई शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए दो (02) जल रिलीज आदेश जारी किए गए थे।

### 5.3 चेन्नई शहर में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए कृष्णा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समिति।

28 नवंबर 2017 को बेंगलुरु में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 10वीं बैठक के अनुसार, चेन्नई शहर में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए कृष्णा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए MoWR, भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति के गठन हेतु दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 का आदेश **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

- I. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तत्कालीन आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय के बीच 1976 और 1977 के समझौतों के प्रासंगिक उद्धरण हैं:
  - (i) "महाराष्ट्र, कर्नाटक और तत्कालीन आंध्रप्रदेश को चेन्नई शहर में पेयजल की आपूर्ति के लिए हर साल 1 जुलाई से 31 अक्टूबर की अवधि के दौरान 5 टीएमसी पानी छोड़ना पड़ता है"।
  - (ii) तमिलनाडु सरकार 1 जुलाई से 31 अक्टूबर की अवधि के दौरान श्रीशैलम जलाशय से एक वर्ष में 15 टीएमसी से अधिक जल नहीं लेगी।
- II. तत्कालीन आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के बीच 1983 के समझौते का प्रासंगिक उद्धरण है:
 

आंध्रप्रदेश जुलाई से अक्टूबर की अवधि के दौरान 8 टीएमसी और जनवरी से अप्रैल की अवधि के दौरान 4 टीएमसी प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की एक बैठक यानि 6वीं बैठक समिति एवं केआरएमबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 23-12-2021 को आयोजित की गई।

समिति की छठी बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- यह बताया गया कि 01.06.2020 से 31.05.2021 की अवधि के दौरान एपी/टीएन सीमा पर 8.116 टीएमसी पानी छोड़ा गया था और यह तेलुगु गंगा परियोजना की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है।
- आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से आगामी वर्ष 2022-23 के लिए जल निकासी योजना कम से कम एक महीने पहले समिति को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
- आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य चालू जल वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए अनुसूची/योजना समिति को प्रस्तुत करने पर सहमत हुए हैं।

- तमिलनाडु राज्य GoAP (APWRIMS) की आधिकारिक वेबसाइट से आवश्यक डेटा प्राप्त कर सकता है, जहां वेलुगोडु, सोमासिला और कंडालेरू जलाशय का डेटा अपलोड किया गया है।  
GoTN  
अधिकारियों ने उल्लेख किया कि वे पूंडी जलाशय में सेंसर आधारित वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली का भी प्रस्ताव कर रहे थे।
- एपी और टीएन राज्यों ने राय दी कि वे अपनी अगली स्थायी तकनीकी समिति की बैठकों में नहरों की परिवहन क्षमता में सुधार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
- समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि खाता निपटान/लागत साझाकरण समिति के दायरे में नहीं है और सुझाव दिया है कि इस मुद्दे को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच मौजूदा स्थायी तकनीकी समिति की बैठकों में उठाया जा सकता है।

## अध्याय -6 प्रशासनिक मामलें

### 6.1 कार्य नियमावली

आंध्रप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 88 के अनुसार, बोर्ड अधिनियम के तहत और वहाँ बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकता है।

- क) बोर्ड की बैठकों के समय और स्थान एवं ऐसी बैठकों में कार्य संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना;
- ख) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन;
- ग) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की नियुक्ति और विनियमन करना ;
- घ) कोई अन्य मामला जिसके लिए बोर्ड द्वारा नियमों को आवश्यक माना जाता है।

तदनुसार, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) ने मसौदा कार्य नियमावली तैयार की, जिसमें बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक नियम, व्यवसाय के संचालन की प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करना, कर्मचारियों की आवश्यकता आदि शामिल हैं।

09.08.2019 को आयोजित कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की 10वीं बैठक में और 09.01.2020 को आयोजित 11वीं बोर्ड बैठक में एजेंडा आइटम 11.5 के रूप में दोनों राज्य सरकारों से पहले के मसौदे पर टिप्पणी प्राप्त करने के बाद कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का एक मसौदा कार्य नियमावली रखा गया था। कार्य नियमावली को अंतिम रूप देने के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए दोनों बोर्डों यानी केआरएमबी और जीआरएमबी की संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

09.01.2020 को आयोजित 11वीं बोर्ड बैठक में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की कार्य नियमावली 2019 को एजेंडा 11.5 के रूप में रखा गया था और कार्य नियमावली को अंतिम रूप देने के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए दोनों बोर्डों (यानी, केआरएमबी और जीआरएमबी) की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

### 6.2 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड वेबसाइट

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) की वेबसाइट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सर्वर पर "krmb.gov.in" डोमेन नाम के साथ होस्ट किया जा रहा है। परियोजना प्राधिकरणों के सभी हितधारकों को इस वेबसाइट पर जलाशय के प्रवाह और बहिर्वाह का दैनिक डेटा डालना आवश्यक है। दोनों राज्यों के जल उपयोग का लेखा-जोखा तैयार करते समय इसी बात पर विचार किया जाता है।

### 6.3 ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस का लक्ष्य नागरिकों को कुशल और किफायती तरीके से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। भारत सरकार ने कई डिजिटल इंडिया घटकों की शुरुआत की है।

डिजिटल इंडिया के निम्नलिखित घटकों को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

**ई-खरीददारी:** सरकार ने 01.04.2016 से 2.00 लाख रुपये की न्यूनतम निविदा मूल्य सीमा के साथ की गई सभी खरीदों की ई-खरीद शुरू करने की पहल की। तदनुसार, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा <https://eprocure.gov.in> के माध्यम से ई-निविदा की प्रक्रिया द्वारा खरीद की जाती है।

**ई-समीक्षा सॉफ्टवेयर:** ई-समीक्षा कैबिनेट सचिवालय में आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए एक वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली है। मंत्रालय के सभी संगठनों में ई-समीक्षा सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के लिए, केआरएमबी ने अपना नोडल अधिकारी को नामित किया था और ई-समीक्षा सॉफ्टवेयर सिस्टम में पंजीकरण के लिए जल शक्ति मंत्रालय को सूचित किया था।

**सरकारी ई-बाजार (GeM):** विभिन्न सरकारी विभागों / संगठनों / सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए **GeM** वन-स्टॉप पोर्टल है। GeM का उद्देश्य खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाना है। सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा GeM के माध्यम से खरीदारी को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में एक नया नियम संख्या 149 जोड़कर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत और अनिवार्य कर दिया गया है। तब से कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में GeM के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाती है। ई-समीक्षा के संबंध में की गई गतिविधियों और अद्यतनों पर मासिक रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही है।

**कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (LIMBS):** LIMBS को ई-गवर्नेंस पहल के एक भाग के रूप में विभिन्न अदालतों / प्राधिकरणों में लंबित सभी मामलों का एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाना है। एक बार पूरा हो जाने के बाद, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और अन्य संगठनों द्वारा संभाले जा रहे सभी अदालतों / अधिकरण मामलों से संबंधित जानकारी एक ही वेब - आधारित ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध होगी। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड वर्ष 2018 से **LIMBS** वेबसाइट पर डेटा अपलोड कर रहा है।

### 6.4 मूलभूत सुविधाएँ / कार्यालय परिसर

बोर्ड के लिए मूलभूत सुविधाएँ / कार्यालय परिसर का प्रदान तेलंगाना सरकार द्वारा जल सौधा बिल्डिंग मंजिल में, एरममंजिल, हैदराबाद में किया गया था। ।

## अध्याय – 7

### वित्तीय मामले

#### 7.1 वित्तीय प्रावधान

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 86 (2) के अनुसरण में, आंध्रप्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार बोर्ड के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सभी खर्चों को पूरा करने के लिए बोर्ड को हर समय आवश्यक धनराशि प्रदान करेगा और ऐसी राशि को संबंधित राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में विभाजित किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार, लाभों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रत्येक राज्य पर निर्दिष्ट करें।

प्रारंभ में, केआरएमबी के संबंध में किए गए व्यय को आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा पीएओ, विजयवाड़ा के माध्यम से एचओडी, मुख्य अभियंता, कृष्णा डेल्टा सिस्टम, विजयवाड़ा के तहत संसाधित किया गया था। हालाँकि, इस प्रक्रिया के माध्यम से बिलों (वेतन बिलों सहित) के समय पर निपटान के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इसलिए 16 दिसंबर, 2015 को आयोजित बोर्ड की तीसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि, दोनों राज्य बजट निधि जमा करेंगे और इस प्रकार बोर्ड को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।

आंध्रप्रदेश सरकार हर साल वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान के अनुसार पूरी राशि जमा करेगी। तेलंगाना सरकार का हिस्सा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जाएगा।

22 अगस्त 2017 को आयोजित बोर्ड की 6वीं बैठक के दौरान, बोर्ड ने कम से कम ₹.10.00 करोड़ का आरक्षित कोष रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड धीरे-धीरे अनुमोदित / आवंटित निधि से बचत से आरक्षित निधि का निर्माण कर सकता है, जो प्रति वर्ष अधिकतम ₹.1.00 करोड़ होगी।

6 जून, 2018 को आयोजित बोर्ड की 8वीं बैठक में, दोनों राज्यों के बीच व्यय के हिस्से के बंटवारे और आंध्र प्रदेश को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से बचने के लिए, जिसमें समय लगता है, इस बात पर सहमति हुई कि, दोनों राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष 2018-19 से बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान समान अनुपात (50:50) में साझा करेंगी।

हालाँकि, 16 अक्टूबर, 2018 को आयोजित बोर्ड की 9वीं बैठक में, मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर, यह निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश राज्य त्रैमासिक रूप से केआरएमबी की पूर्ण बजट

आवश्यकता जारी करेगा। तेलंगाना सरकार उचित लेखांकन के लिए बाद में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से अपने हिस्से का 50% प्रतिपूर्ति करेगा। इसके साथ ही बोर्ड की पिछली बैठक का निर्णय निरस्त हो गया है।

बचत बैंक खाता बोर्ड सचिवालय द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाएगा क्योंकि अध्यक्ष चिन्हित कार्यों के लिए राशि का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। वह बोर्ड सचिवालय के भीतर वित्त के संचालन को सौंप सकता है।

सभी लेनदेन दो हस्ताक्षरों के तहत संयुक्त रूप से किए जाएंगे। निदेशक (वित्त) और आहरण एवं संवितरण अधिकारी हस्ताक्षरकर्ता हैं।

वर्ष के अंत में जो अनुपयोगी बची धनराशि हो, वे सुरक्षित है और इसे अगले वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

बोर्ड सचिवालय खर्चों का वार्षिक लेखा-जोखा बोर्ड के समक्ष रखेगा। बोर्ड के खाते राज्य / केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड द्वारा 18.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान GoTS ने 6.00 करोड़ रुपये और GoAP ने 9.00 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा बजट अनुमान, जारी धनराशि और किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमान, प्राप्त धनराशि एवं व्यय का विवरण :

(रू. लाखों में)

क्र.सं	ब्यौरा	राशी
I.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान	1800.00
II.	2020-21 के दौरान जारी बजट की राशि	1500.00
III.	2020-21 के दौरान व्यय	661.69
IV.	31.3.2021 को शेष पिछले वर्ष की बचत राशि सहित (भारत सरकार से अनुदान को छोड़कर)	1418.67

**नोट:** MOWR, RD & GR पत्र संख्या : R.160011/8/2014-Pen.Riv/009 दि : 16.12.2014 के माध्यम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार से धन प्राप्त करने पर बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली प्रारंभिक राशि के रूप में रू.1.00 करोड़ का एकमुश्त अनुदान प्राप्त हुई थी।

## 7.2 खरीददारी

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और स्थानीय बाजार के माध्यम से करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खरीदी गए प्रमुख मदों में कंप्यूटर और सहायक उपकरण थे।

## 7.3 लेखा परीक्षण (ऑडिट)

पी. विश्वनाथ एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हैदराबाद को वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए केआरएमबी के व्यय लेनदेन पर आंतरिक ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने आंतरिक ऑडिट पूरा कर लिया था और 27.05.2021 को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केआरएमबी के आंतरिक लेखापरीक्षित खातों का लेखापरीक्षा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (एएफ एंड डब्ल्यूआर), चेन्नई शाखा कार्यालय, चेटपेट, चेन्नई के कार्यालय द्वारा किया गया था। अलग ऑडिट रिपोर्ट के उत्तर केआरएमबी द्वारा प्रधान निदेशक ऑडिट (एएफ एंड डब्ल्यूआर), चेटपेट, चेन्नई के कार्यालय उप निदेशक को प्रस्तुत किए गए थे। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

वित्त वर्ष के लिए केआरएमबी का लेनदेन ऑडिट 2014-15 से 2020-21 तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (एएफ एंड डब्ल्यूआर), चेन्नई शाखा कार्यालय, चेटपेट, चेन्नई द्वारा 06.01.2022 से 20.01.2022 तक आयोजित किए गए थे।

## अध्याय -8 तकनीकी मामले

### 8.1 जल प्रबंधन

#### आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे की व्यवस्था।

कृष्णा बेसिन में आंध्रप्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के बीच पानी के एक अस्थायी वितरण पर 18-19 जून, 2015 को नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, आरडी और जीआर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति हुई थी (बैठक का कार्यवृत्त की एक प्रति अनुलग्नक-V पर है)। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) द्वारा जल उपयोग के विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में आंध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और तेलंगाना सरकार के आई और सीएडी विभाग के प्रधान सचिव ने भाग लिया।

बैठक में, 811 टीएमसी जल (तत्कालीन आंध्रप्रदेश राज्य को विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग के लिए केडब्ल्यूडीटी द्वारा (आवंटित ब्लॉक) की मात्रा को तेलंगाना के लिए 298.96 टीएमसी और आंध्र प्रदेश के लिए 512.04 टीएमसी जल के रूप में साझा करने पर सहमति हुई। इस बात पर सहमति हुई कि वर्तमान वर्ष के लिए 811 टीएमसी के आवंटन के बाद उपलब्ध पानी की मात्रा को आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा। इसी तरह, 811 टीएमसी से नीचे का घाटा भी तदनुसार साझा किया जाएगा। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच अनुपात 63.13: 36.87 है।

18-19 जून, 2015 को संपन्न बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों राज्यों के मुख्य अभियंताओं और केआरएमबी के सदस्य सचिव सहित एक तीन सदस्यीय समिति समय-समय पर पानी की उपलब्धता और आवश्यकताओं का आकलन करते हुए राज्यों द्वारा उठायी जानेवाली जल संबंधी मांगों का निपटान करेगी। केआरएमबी द्वारा लिया गया निर्णय संबंधित राज्य परियोजना अधिकारियों द्वारा लागू किया जाएगा।

21.09.2016 को आयोजित पहली शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान, दोनों राज्य 2015-16 और वर्ष 2016-17 के लिए भी जल बंटवारे की कार्यशील व्यवस्था जारी रखने पर सहमत हुए।

04.11.2017 को आयोजित बोर्ड की 7वीं बैठक में, बोर्ड ने जल वर्ष 2017-18 के लिए एपी और टीएस के लिए कृष्णा जल को 66:34 के अनुपात में साझा करने का निर्णय लिया।

इसके बाद, जल वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए 66:34 (एपी : टीएस) का अनुपात अपनाया गया है।

## 8.2 जल उपयोग का विवरण

जल वर्ष 2021-22 के दौरान दोनों राज्यों द्वारा जल का उपयोग।

### कृष्णा बेसिन में उपयोगिताएँ:

कृष्णा बेसिन में, जल वर्ष 2021-22 के दौरान, दोनों राज्यों द्वारा कुल उपयोग 886.892 टीएमसी है, जिसमें से आंध्रप्रदेश का उपयोग 621.841 टीएमसी और तेलंगाना राज्य का उपयोग 265.051 टीएमसी है।

### दो कॉमन जलाशयों में उपयोग:

जल वर्ष 2021-22 के दौरान, दोनों राज्यों द्वारा नीलम संजीव रेड्डी सागर (श्रीशैलम) और नागार्जुन सागर परियोजना से 707.589 टीएमसी पानी लिया गया। इसमें से 175.151 टीएमसी श्रीशैलम जलाशय से और 532.438 टीएमसी नागार्जुन सागर से निकाली गई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा इन जलाशयों से नहर / योजना-वार जल की निकासी **अनुलग्नक -VI** में संलग्न है।

श्रीशैलम और नागार्जुनसागर परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2021-22 के दौरान जलाशय स्तर और भंडारण **प्लेट-I** और **प्लेट-II** में दर्शाए गए हैं।

## 8.3 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के तहत टेलीमेट्री प्रणाली का कार्यान्वयन

### चरण – 1

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने 21-22 जून, 2016 को आयोजित MoWR, RD & GR की बैठक और 21 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, कृष्णा बेसिन में आंध्रप्रदेश और तेलंगाना की विभिन्न परियोजनाओं के प्रवाह और बहिर्वाह का वास्तविक आंकड़े रखने के लिए टेलीमेट्री प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

कुल मिलाकर, चरण-I में जूराला, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर परियोजनाओं के विभिन्न स्थानों पर 18 टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित किए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र सं.	टेलीमेट्री स्टेशन का नाम	सेंसार का प्रकार	एपी / टीएस क्षेत्रीय मंडल की प्रभारी
1	अक्कमपल्ली बैलेंसिंग जलाशय से जुड़ने वाली लिंक नहर के किमी 1.10 पर एएमआरपी लिफ्ट योजना	लेवल सेंसर	एएमआर एसएलबीसी डिविजन, अंगडिपेटा।
2	नागार्जुन सागर परियोजना (एनएसपी) बांध पर डायवर्जन सुरंग इंटेक टॉवर		बांध रखरखाव प्रभाग, हिल कॉलोनी, एनएसपी बांध
3	हेडरेगुलेटर के एनेस्पी राईट बैंक नहर 0.44 कीमी पर	लेवल सह वेग सेंसर	निगरानी प्रभाग, लिंगमगुंटला

4	सुरंग में पानी के प्रवेश बिंदु के पास एनएसपी बायीं तट नहर		एनएससी निगरानी प्रभाग, टेकुलपल्ली, खम्मम
5	एनएसपी एलबीसी के किमी 136.345. पर अपस्ट्रीम में पालेरू जलाशय इनकी संरचना	लेवल सह वेग सेंसर	
6	एनएसएलसी और पावर हाउस आवुटलेट के संगम से 0.20 किमी की दूर पर पालेरू जलाशय	लेवल सेंसर	
7	एनएसपी एलबीसी किमी 101.362 पर आंध्रप्रदेश तेलंगाना सीमा	लेवल सेंसर	एनएसएलबीसी ओ एंड एम डिवीज़न, नुज़िवीडु
8	महात्मा गांधी कलवाकुर्थी लिफ्ट इरिगेशन योजना (एमजीकेएलआईएस) सिस्टर्न पर ।	लेवल सेंसर	एमजीकेएलआईएस डिवीजन-1, नागर कर्नूल, महबूब नगर
9	श्रीशैलम जलाशय ब्लॉक 17/18 के पास		बाँध रखरखाव प्रभाग, एनएसआरएसएसपी
10	पोतिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर के एसआरएमसी के एसएलबी किमी 12.265 पर	लेवल सह वेग सेंसर	टीजीपी डिस्ट्रीब्यूटरी डिविजन-1, नंद्याल
11	हंद्री नीवा सुजल स्रवंति (HNSS) LI योजना पर पुराने पंप हाउस के कल्वर्ट के पास किमी (-) 1.62		प्रभाग-02, एचएनएसएस, डब्ल्यूआरडी, कर्नूल
12	जूराला जलाशय	लेवल सेंसर	पीजेपी बांध डिवीजन नंबर-2, नंदिमला
13	जूराला दाहिनी मुख्य नहर हेड रेगुलेटर के पास		पीजेपी निष्पादन प्रभाग क्रमांक-2, गद्वाल
14	जूराला बायीं मुख्य नहर हेड रेगुलेटर के पास		पीजेपी बांध डिवीजन नंबर-2, नंदिमला
15	जूराला बाईं समानांतर नहर हेड रेगुलेटर के पास	लेवल सेंसर	आरबीएल-II, एचडब्ल्यू और नहर प्रभाग, संगमबंडा कैम्प, मक्तल, महबूबनगर।
16	भीमा एलआई योजना - I लिफ्ट बिंदु पर		
17	कोइल सागर एलआई योजना लिफ्ट के पास		
18	नेट्टमपाडु एलआई योजना लिफ्ट बिंदु पर	लेवल सह वेग सेंसर	पीजेपी निष्पादन प्रभाग क्रमांक-2, गद्वाल

चरण -1 टेलीमेट्री स्टेशनों के सभी 18 नंबर 2 साल की वारंटी और 5 साल की एएमसी के अंतर्गत आते हैं और एजेंसी मेसर्स मेक्ट्रोनिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पुणे वारंटी और एएमसी का कार्य कर रही है।

सभी 18 टेलीमेट्री स्टेशनों का रिमोट डेटा केआरएमबी, हैदराबाद के मॉडल केंद्र में प्राप्त किया जा रहा है।



**पोतिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर**  
**अनुप्रवाह पर गैर-संपर्क जल स्तर सह वेग सेंसर**



नागार्जुन सागर परियोजना जलाशय में टेलीमेट्री स्टेशन



कोयिल सागर एलआईएस में टेलीमेट्री स्टेशन

## 8.4 जल विद्युत

दोनों राज्यों में कृष्णा नदी पर, जल विद्युत संयंत्र प्रियदर्शनी जुराला, लोअर जुराला, श्रीशैलम दायां किनारा पावर हाउस, श्रीशैलम लेफ्ट बैंक पावर हाउस, नागार्जुन सागर बांध पावर हाउस, नागार्जुन सागर दाहिनी कैनाल पावर हाउस, नागार्जुन सागर बाएं कैनाल पावर हाउस, नागार्जुन सागर पूँछ तालाब बिजली घर और पुलिचिंतला बिजली घर स्थित हैं। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण ऊर्ध्व प्रवाह से अनुप्रवाह तक स्थान के क्रम में **अनुलग्नक - VII** में दिया गया है। वर्तमान में, इन्हें संयंत्रों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा संचालित किया जाता है।

18-19 जून, 2015 को अतिरिक्त सचिव, एमओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, नई दिल्ली द्वारा ली गई बैठक में दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए कि बिजली उत्पादन के लिए रिलीज करते समय नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जलाशय के लिए प्रतिबद्ध उपयोग **अनुलग्नक - V** के परिशिष्ट में जो उल्लिखित है वो सुनिश्चित किया जा सकता है।

**जल वर्ष 2021-22 के दौरान कृष्णा नदी पर विभिन्न बिजली संयंत्रों का जल विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट) निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:**

महीना	प्रियदर्शनी जुराला	निचली जुराला	श्रीशैलम आरबी	श्रीशैलम एल बी	नागार्जुन सागर परियोजना	नागार्जुन सागर आरबीसी	नागार्जुन सागर एलबीसी	एन एस टेल पाँड	पुलिचिंतला
जून-21	24.770	28.980	0.313	55.340	51.260	0.000	0.000	2.719	0.300
जुलाई-21	33.410	34.040	66.297	286.460	198.30	0.000	0.000	14.337	30.480
अगस्त-21	63.550	67.780	235.095	472.060	533.490	29.191	21.690	28.985	51.740
सितंबर-21	106.190	122.910	217.842	408.000	410.940	37.156	16.820	28.671	59.160
अक्टूबर-21	92.900	95.380	443.316	501.050	558.400	45.560	30.030	27.558	63.270
नवंबर-21	10.200	13.080	186.169	148.090	257.880	34.807	13.180	17.453	39.030
दिसंबर-21	4.040	6.030	76.689	53.100	10.680	38.864	16.920	5.126	14.560
जनवरी-22	0.000	0.530	133.835	91.270	30.710	35.625	18.490	1.694	12.960
फरवरी - 22	0.000	0.000	60.331	41.080	62.770	29.469	20.430	1.715	17.210
मार्च-22	0.000	0.370	1.683	0.000	81.650	25.303	10.770	6.581	14.560
अप्रैल-22	0.000	0.000	0.000	0.230	48.750	7.257	1.910	1.705	11.850
मई-22	0.000	0.000	0.000	0.000	38.730	1.253	0.000	0.782	7.910
<b>कुल</b>	<b>335.060</b>	<b>369.100</b>	<b>1421.570</b>	<b>2056.68</b>	<b>2283.560</b>	<b>284.485</b>	<b>150.24</b>	<b>137.326</b>	<b>323.030</b>

बिजली उत्पादन के लिए श्रीशैलम और नागार्जुनसागर परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2021-22 के दौरान पानी का उपयोग **प्लेट-III और प्लेट-IV** में दिया गया है।

### 8.5 अंतरराज्यीय परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत का विनियमन

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85(8)(बी) के अनुसार, केआरएमबी को वर्तमान आंध्रप्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के साथ किसी भी समझौते या व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्युत् वितरण के प्रभारी प्राधिकारी को उत्पन्न विद्युत् की आपूर्ति का विनियमन करना आवश्यक है।

तुंगभद्रा परियोजना को पूरा करने और इसके संचालन और रखरखाव के लिए आंध्रप्रदेश राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 66 की उपधारा (4) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अलग "तुंगभद्रा बोर्ड" का गठन किया गया है।

**तुंगभद्रा अंतरराज्यीय विद्युत परियोजना** में तुंगभद्रा नदी पर दो अंतरराज्यीय विद्युत गृह (जैसे हम्पी विद्युत गृह - 4x9 मेगावाट और तुंगभद्रा बांध विद्युत गृह - 4x9 मेगावाट) हैं। इससे पूर्व उत्पादित बिजली कर्नाटक और अविभाजित आंध्रप्रदेश राज्यों के बीच साझा की जा रही थी।

### 8.6. तकनीकी समितियाँ

**I. आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए कृष्णा नदी पर मुख्य स्टेम परियोजनाओं से बहनेवाले मानसून अवधि के दौरान अधिशेष पानी के विनियमन के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया।**

21.09.2021 को आयोजित बोर्ड की 14वीं बैठक के दौरान, "बाढ़ की अवधि के दौरान जब सभी बांध अधिशेष होते हैं, तब दोनों राज्यों द्वारा किए गए उपयोग की छूट" पर चर्चा की गई थी, जिसमें यह याद किया गया था कि कृष्णा नदी पर मुख्य स्टेम परियोजनाओं से बहने वाले मानसून अवधि के दौरान अधिशेष पानी के विनियमन के लिए डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मुख्य अभियंता, आईएमओ, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हालाँकि, समिति ने दोनों राज्यों से अपेक्षित डेटा की कमी के कारण अपनी सिफारिश प्रस्तुत नहीं की है।

बैठक के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि अधिशेष अवधि के दौरान मोड़े गए सभी जल का डेटा दर्ज किया जाना चाहिए और लेखा रखा जाना चाहिए।

**II. आवंटन की योजना-ए के तहत केडब्ल्यूडीटी-1 द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में तेलंगाना द्वारा पानी के अप्रयुक्त हिस्से को अगले जल वर्ष में ले जाना और पिछले जल वर्ष में लेखांकन**

विषय वस्तु पर 21.09.2021 को आयोजित बोर्ड की 14वीं बैठक के दौरान, अध्यक्ष, केआरएमबी ने

राय दी कि यदि अप्रयुक्त पानी को किसी एक राज्य के हिस्से को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सामान्य जलाशय में संग्रहीत किया जाता है, तो इससे अगले वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा आम हिस्सेदारी के लिए उपलब्ध भंडारण का शुद्ध पानी कम हो जाएगा।

सचिव, डब्ल्यूआरडी, जीओएपी ने तेलंगाना राज्य की पेयजल आवश्यकताओं के मामले के आधार पर जाने की बात कही और कहा कि जीओएपी सहयोग का विस्तार करेगा, जैसे वे अतीत में दोनों राज्यों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए सहयोग करते रहे हैं।

विशेष मुख्य सचिव, I&CAD, GoTS ने कहा कि कृष्णा नदी की गतिशीलता थोड़ी अलग है और ज्यादातर इसमें देर से प्रवाह आएगा। मौजूदा परिदृश्य में, उन्होंने बोर्ड से निर्णय लेने का अनुरोध किया कि, तेलंगाना को कम से कम पीने के पानी की आवश्यकताओं के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि बोर्ड को सूचित किया गया है।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, दोनों राज्य प्रत्येक मामले के आधार पर पेयजल आवश्यकता के मुद्दे पर विचार करने और एक-दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

### III. समन्वय समिति का गठन

राजपत्र अधिसूचना एसओ 2842(ई) दिनांक: 15.07.2021 के कार्रवाई योग्य खंडों के समयबद्ध कार्यान्वयन और संचालन में केआरएमबी कार्यालय और दोनों राज्य सरकारों के संबंधित विभागों / निगमों को सुविधा प्रदान करने के लिएअध्यक्ष, केआरएमबी के अनुमोदन से ओ.एम. दिनांक 02.08.2021 द्वारा एक "समन्वय समिति" का गठन किया गया था।

दिनांक 03.08.2021 को "समन्वय समिति" की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें दिनांक 05.08.2021 को जारी कार्रवाई योग्य धाराओं और कार्यवृत्त पर चर्चा की गई। इस बैठक में GoTS के सदस्यों की कोई भागीदारी नहीं थी. केआरएमबी को I&CAD विभाग, GoTS से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें पूर्ण बोर्ड बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया।

13वीं (आपातकालीन) बोर्ड बैठक 9 अगस्त 2021 को आयोजित की गई जिसमें कार्रवाई योग्य खंडों पर चर्चा की गई। इस बैठक में GoTS के सदस्यों की कोई भागीदारी नहीं थी। दोनों बैठकों में आंध्र प्रदेश सरकार के सदस्यों ने भाग लिया। 13वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त 16 अगस्त, 2021 को जारी किया गया।

अधिसूचना में कार्रवाई योग्य खंड अर्थात् 1(ई), 1 (जी), 1(आई), 1(जे), 1(के), 1(एल),2(ए), 2(बी), 2(डी) ), 2(ई), 2(एफ), और 2(जी) को बोर्ड के सदस्यों के लाभ के लिए सदस्य सचिव द्वारा शब्दशः प्रस्तुत किया गया था

### समन्वय समिति का नामकरण एवं पुनर्गठन:

14वीं बोर्ड बैठक में, GoTS के सदस्यों ने कहा कि समन्वय समिति का नाम और संविधान GoTS को स्वीकार्य नहीं है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि इसका नाम बदलकर "उप-समिति" किया जा सकता है और समिति में राज्यों के प्रतिनिधित्व के स्तर को कम किया जा सकता है। तीन केआरएमबी सदस्यों के अलावा, दोनों राज्यों में अंतर-राज्यीय जल मामलों से निपटने वाले मुख्य अभियंता और दोनों राज्यों में जेनको के मुख्य अभियंता सदस्य होंगे। दोनों राज्यों के सदस्यों ने राय दी कि ट्रांसको के अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जेनको के सदस्य सभी पहलुओं का ध्यान रखेंगे। बोर्ड में दोनों राज्यों के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि उप-समिति में नामित सदस्य उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और कार्रवाई योग्य खंडों पर अपेक्षित इनपुट समय पर प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष, केआरएमबी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि जीओएपी और जीओटीएस के बोर्ड सदस्य अनुसूची-2 के तहत सूचीबद्ध जलविद्युत स्टेशनों के संबंध में कार्रवाई योग्य खंडों के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर एपीजेनको और टीएसजेनको के साथ जुड़ने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। केआरएमबी कार्यालय उप-समिति के संबंध में एक संशोधित ओएम जारी करेगा। उप-समिति द्वारा तैयार रोड-मैप को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

## अध्याय-9

# संसदीय प्रश्न, आरटीआई, वीआईपी संदर्भ, क्षमता निर्माण और अदालती मामले

### 9.1 संसदीय प्रश्न

वर्ष 2020-2021 के दौरान, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने उनतीस (29) संसदीय प्रश्नों (लोकसभा और राज्य सभा) के उत्तर तैयार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण को प्रासंगिक जानकारी / इनपुट प्रस्तुत किए।

### 9.2 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

केआरएमबी में आरटीआई अधिनियम, 2005 को लागू करने के लिए, अधीक्षण अभियंता को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के लिए केंद्रीय केंद्र सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया था और सदस्य सचिव को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को विभिन्न व्यक्तियों / संगठनों से पचास (44+6=50) आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी आवेदकों को जवाब भेज दिए गए हैं।

### 9.3 वीआईपी संदर्भ:

केआरएमबी ने वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त एक (1) वीआईपी संदर्भों का जवाब देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण को प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत की है।

### 9.4 अदालती मामले

जल वर्ष 2021-2022 के दौरान, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), दक्षिणी क्षेत्र (एसजेड), चेन्नई में दायर 4 मामलों को केआरएमबी को भेजा गया था। काउंटर दाखिल कर दिए गए हैं और मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

## अदालती मामलों की स्थिति प्रतिवेदन

क्रम सं.	केस सं.	LIMBS सं.	अदालत का नाम	भरने की तारीख	शामिल मुद्दे	टिप्पणी
1	एम.ए. क्रमांक 02/2021 & ओ.ए. क्रमांक 71/2020 में एम.ए. क्रमांक 03/2021		NGT, SZ चेन्नई	24-06-2021	उपरोक्त विविध आवेदन आवेदक द्वारा इस ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दायर किया गया है और साथ ही इस ट्रिब्यूनल के समक्ष उनके द्वारा पहले दिए गए आवेदन, O.A. 2020 की संख्या 71 2020 में एम.ए. नंबर 06 में दिए गए कार्यों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए दायर किया गया क्योंकि वे अभी भी इस ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशों का पालन किए बिना अपनी परियोजना के तहत निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के लिए प्रारंभिक कार्य की आड़ में, वे वास्तव में वास्तविक कार्य को ही आगे बढ़ा रहे हैं।	17-12-2021 को फैसला सुनाया गया रिपोर्ट की प्रतीक्षा: एमओईएफ और सीसी और संयुक्त समिति को विचार के लिए चार महीने की अवधि के भीतर इस ट्रिब्यूनल को अपनी संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

क्रम सं.	केस सं.	LIMBS सं.	अदालत का नाम	भरने की तिथि	शामिल मुद्दे	टिप्पणी
2.	ओ.ए. क्रमांक 137/2021	920915	NGT, SZ चेन्नई	27-06-2021	पूर्व पर्यावरण और वन मंजूरी (जीएनएसएस) के बिना जीओ संख्या 444 और 461 के तहत लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं और जलाशयों को संतुलित करने से जीओएपी को रोकना	दिनांक 14.02.2022 को निस्तारण किया गया
3.	ओ.ए. क्रमांक 148/2021 अई .ए. क्रमांक 35/2022	920921	NGT,SZ, चेन्नई	05-07-2021	PRLIS का अनधिकृत निर्माण, बिना किसी आवंटन - KWDI-I और II के पुरस्कारों के अनुसार, ARR अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के विपरीत, EIA के तहत अंतिम अनुमति के बिना	अंतरिम आदेश सुनाया गया: 29 अक्टूबर, 2021
4.	ओ.ए. क्रमांक 212/2021 अई .ए. क्रमांक 35/2022	920927	NGT,SZ, चेन्नई	21-09-2021	यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य के आवेदक द्वारा दायर किया गया है, जिसमें डिंडी लिफ्ट सिंचाई योजना के संबंध में ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप की मांग की गई है, जो तेलंगाना राज्य द्वारा आम जलाशय, अर्थात् श्रीशैलम जलाशय परियोजना और कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे से शुरू की गई है। जिसे दोनों राज्यों को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार उपयोग करने की अनुमति दी गई थी	अंतरिम आदेश सुनाया गया: 29 अक्टूबर, 2021

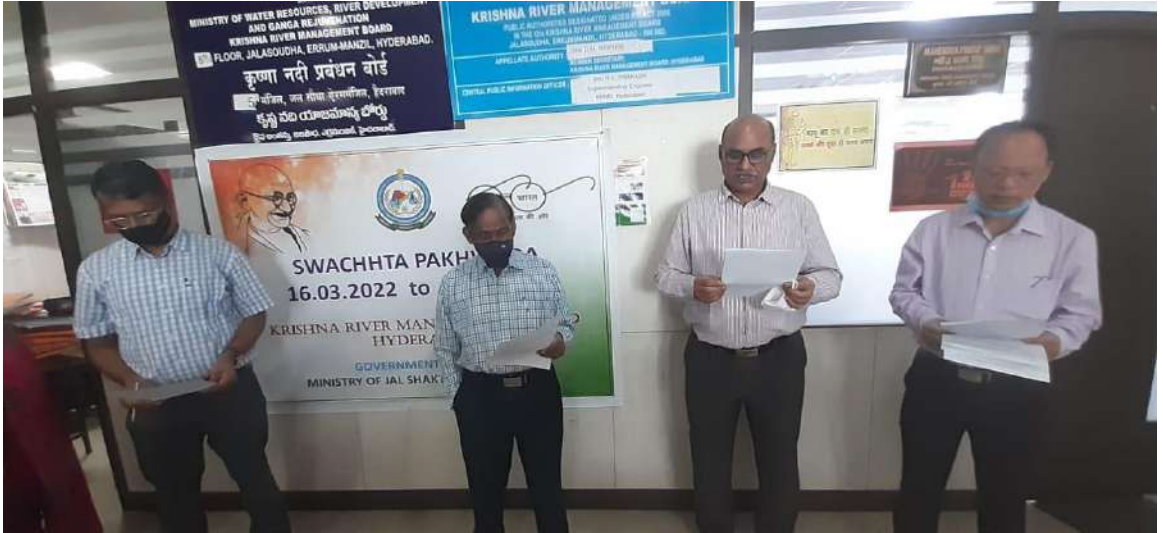
## अध्याय – 10 अन्य गतिविधियाँ

### 10.1 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस:

माननीय प्रधान मंत्री ने महामारी (कोविड-19) की मौजूदा स्थितियों के कारण "कल्याण के लिए योग" की थीम और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 (21.06.2021) मनाने का स्पष्ट आह्वान किया है। केआरएमबी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को वीडियो लिंक का पालन करके योग का अभ्यास कराया गया।

### 10.2 स्वच्छता पखवाड़ा:

MoJS, DoWR, RD&GR के निर्देशों के अनुसार पत्र क्रमांक बी-11011/3/2021-जीए, दिनांक: 04.03.2022, स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन 16.03.2022 को केआरएमबी, हैदराबाद में किया गया। अध्यक्ष श्री एम. पी. सिंह द्वारा केआरएमबी के अधिकारियों और कर्मचारियों को अंग्रेजी और हिंदी में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में 16 से 31 मार्च, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा-2022 के दौरान कार्यालय कक्षों और गलियारों की विशेष सफाई, विश्व जल दिवस कार्यशाला, स्वच्छता कार्यशाला और कार्यालय उपकरणों की सफाई पर विशेष अभियान जैसी गतिविधियाँ शुरू की गईं।

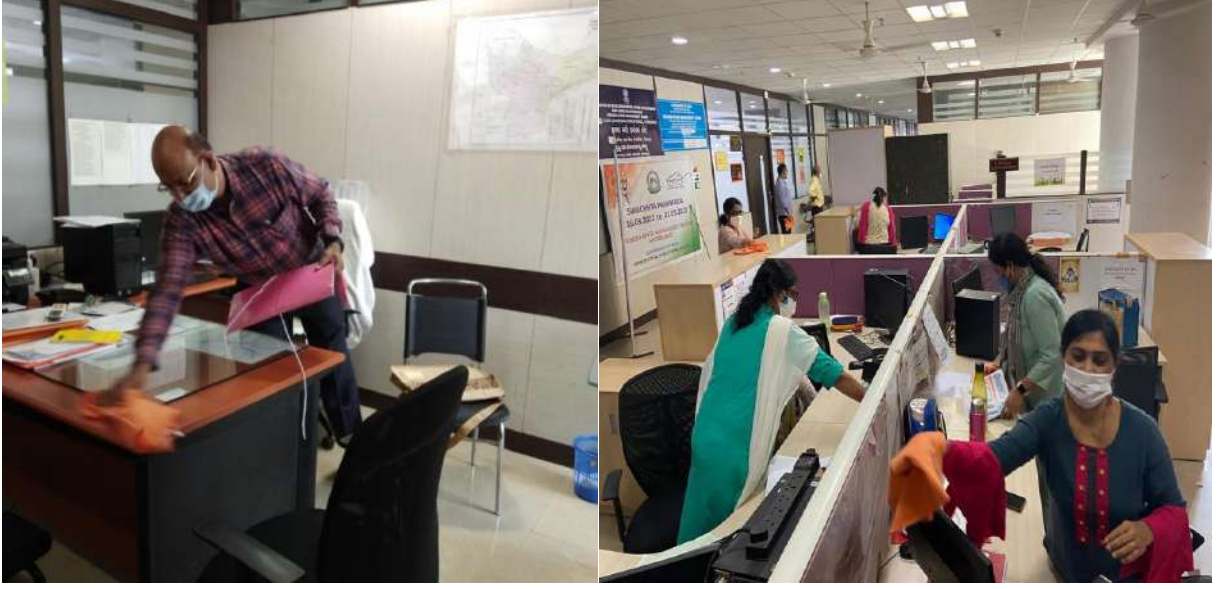


केआरएमबी के अध्यक्ष श्री एम. पी. सिंह ने स्वच्छता शपथ दिलाई



केआरएमबी अधिकारियों / कर्मचारियों ने ली स्वच्छता की शपथ ।





कार्यालय परिसर की सफाई, पुराने अखबारों, कच्चे कागजात का निपटान और सभी पुरानी फाइलों की समीक्षा और छंटनी



22.03.2022 को विश्व जल दिवस कार्यशाला में सदस्य सचिव, अध्यक्ष और सदस्य (विद्युत)।



केआरएमबी के अधिकारियों द्वारा विश्व जल दिवस की शपथ।



केआरएमबी के अधिकारियों द्वारा विश्व जल दिवस की शपथ।



अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य (विद्युत) और सदस्य  
25.03.2022 को स्वच्छता कार्यशाला में भाग ले रहे हैं।



स्वच्छता कार्यशाला में भाग लेते केआरएमबी के अधिकारी



अध्यक्ष, केआरएमबी



**सदस्य सचिव और सदस्य (विद्युत), केआरएमबी 25.03.2022 को केआरएमबी कार्यालय में कार्यालय उपकरणों की सफाई पर विशेष अभियान में भाग लेना।**

### **10.3 क्षेत्र संदर्शन:**

केआरएमबी के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना दिनांक 15.07.2021 के परिणामस्वरूप, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर दिनांक 12.09.2021 के माध्यम से केआरएमबी में तैनात दो सीडब्ल्यूईएस समूह 'ए' अधिकारी (मुख्य अभियंता), दिनांक 15.07.2021 की अधिसूचना में उल्लिखित विभिन्न परियोजनाओं का क्षेत्राधिकार के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की देखभाल के लिए और सुचारू रूप से अधिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए केआरएमबी में शामिल हुए।

दोनों मुख्य अभियंता 25 और 26 अक्टूबर, 2021 को श्रीशैलम परियोजना स्थल पर आयोजित चौथी उप-समिति की बैठक में और 15 और 16 नवंबर, 2021 को नागार्जुन सागर परियोजना स्थल पर आयोजित 5वीं उप-समिति की बैठक में शामिल हुए।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—14

REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—14



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 2014/ फाल्गुन 10, 1935 (शक)  
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 2014/PHALGUNA 10, 1935 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

### (Legislative Department)

*New Delhi, the 1st March, 2014/Phalguna 10, 1935 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 1st March, 2014, and is hereby published for general information:—

### THE ANDHRA PRADESH REORGANISATION ACT, 2014

No. 6 OF 2014

[1st March, 2014.]

An Act to provide for the reorganisation of the existing State of Andhra Pradesh and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

#### PART I

##### PRELIMINARY

1. This Act may be called the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) “appointed day” means the day which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

(b) “article” means an article of the Constitution;

(c) “assembly constituency”, “council constituency” and “parliamentary constituency” have the same meanings as in the Representation of the People Act, 1950;

(5) The report of the Andhra Pradesh Public Service Commission as to the work done by the Commission in respect of any period prior to the appointed day shall be presented under clause (2) of article 323 to the Governors of the States of Andhra Pradesh and Telangana and the Governor of the State of Andhra Pradesh shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining as far as possible, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State of Andhra Pradesh and it shall not be necessary to cause such report or any such memorandum to be laid before the Legislative Assembly of the State of Telangana.

PART IX

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES

Apex Council for Godavari and Krishna river water resources and their Management Boards.

**84. (1)** The Central Government shall, on and from the appointed day, constitute an Apex Council for the supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board.

(2) The Apex Council shall consist of—

- (a) Minister of Water Resources, Government of India—Chairperson;
- (b) Chief Minister of State of Andhra Pradesh—Member;
- (c) Chief Minister of State of Telangana—Member.

(3) The functions of the Apex Council shall include—

- (i) supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;
- (ii) planning and approval of proposals for construction of new projects, if any, based on Godavari or Krishna river water, after getting the proposal appraised and recommended by the River Management Boards and by the Central Water Commission, wherever required;
- (iii) resolution of any dispute amicably arising out of the sharing of river waters through negotiations and mutual agreement between the successor States;
- (iv) reference of any disputes not covered under Krishna Water Disputes Tribunal, to a Tribunal to be constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956.

33 of 1956.

Constitution and functions of River Management Board.

**85. (1)** The Central Government shall constitute two separate Boards to be called the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board (to be known as the Board), within a period of sixty days from the appointed day, for the administration, regulation, maintenance and operation of such projects, as may be notified by the Central Government from time to time.

(2) The headquarters of Godavari River Management Board shall be located in the successor State of Telangana and of the Krishna River Management Board shall be located in the successor State of Andhra Pradesh.

(3) The Godavari River Management Board and Krishna River Management Board shall be autonomous bodies under the administrative control of the Central Government, and shall comply with such directions as may, from time to time, be given to them by the Central Government.

(4) Each Board shall consist of the following Chairperson and Members, namely:—

- (a) a Chairperson not below the rank or level of Secretary or Additional Secretary to the Government of India to be appointed by the Central Government;

(b) two members, to be nominated by each of the successor States, of which one shall be the technical member not below the rank of Chief Engineer and the other administrative member to represent the concerned States;

(c) one expert to be nominated by the Central Government.

(5) Each Board shall have a full-time Member Secretary, not below the rank of Chief Engineer in the Central Water Commission, to be appointed by the Central Government.

(6) The Central Government shall create such number of posts of the rank of Chief Engineer in the Central Water Commission, as it considers necessary.

50 of 1968. (7) Each Board shall be assisted in the day to day management of reservoirs by the Central Industrial Security Force constituted under the Central Industrial Security Force Act, 1968, on such terms and conditions as the Central Government may specify.

(8) The functions of each Board shall include—

(a) the regulation of supply of water from the projects to the successor States having regard to—

33 of 1956. (i) awards granted by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956;

(ii) any agreement entered into or arrangement made covering the Government of existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(b) the regulation of supply of power generated to the authority in-charge of the distribution of power having regard to any agreement entered into or arrangement made covering the Government of the existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(c) the construction of such of the remaining on-going or new works connected with the development of the water resources projects relating to the rivers or their tributaries through the successor States as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette;

33 of 1956. (d) making an appraisal of any proposal for construction of new projects on Godavari or Krishna rivers and giving technical clearance, after satisfying that such projects do not negatively impact the availability of water as per the awards of the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 for the projects already completed or taken up before the appointed day; and

(e) such other functions as the Central Government may entrust to it on the basis of the principles specified in the Eleventh Schedule.

**86. (1)** The Board shall employ such staff as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions under this Act and such staff shall, at the first instance, be appointed on deputation from the successor States in equal proportion and absorbed permanently in the Board.

Staff of the  
Management  
Board.

(2) The Government of the successor States shall at all times provide the necessary funds to the Board to meet all expenses (including the salaries and allowances of the staff) required for the discharge of its functions and such amounts shall be apportioned between the States concerned in such proportion as the Central Government may, having regard to the benefits to each of the said States, specify.

(3) The Board may delegate such of its powers, functions and duties as it may deem fit to the Chairman of the said Board or to any officer subordinate to the Board.

(4) The Central Government may, for the purpose of enabling the Board to function efficiently, issue such directions to the State Governments concerned, or any other authority, and the State Governments, or the other authority, shall comply with such directions.

Jurisdiction of Board.

**87. (1)** The Board shall ordinarily exercise jurisdiction on Godavari and Krishna rivers in regard to any of the projects over headworks (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines necessary to deliver water or power to the States concerned, as may be notified by the Central Government, having regard to the awards, if any, made by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956.

33 of 1956.

(2) If any question arises as to whether the Board has jurisdiction under sub-section (1) over any project referred thereto, the same shall be referred to the Central Government for decision thereon.

Power of Board to make regulations.

**88.** The Board may make regulations consistent with the Act and the rules made thereunder, to provide for—

- (a) regulating the time and place of meetings of the Board and the procedure to be followed for the transaction of business at such meetings;
- (b) delegation of powers and duties of the Chairman or any officer of the Board;
- (c) the appointment and regulation of the conditions of service of the officers and other staff of the Board;
- (d) any other matter for which regulations are considered necessary by the Board.

Allocation of water resources.

**89.** The term of the Krishna Water Disputes Tribunal shall be extended with the following terms of reference, namely:—

- (a) shall make project-wise specific allocation, if such allocation have not been made by a Tribunal constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956;
- (b) shall determine an operational protocol for project-wise release of water in the event of deficit flows.

33 of 1956.

*Explanation.*—For the purposes of this section, it is clarified that the project specific awards already made by the Tribunal on or before the appointed day shall be binding on the successor States.

Polavaram Irrigation Project to be a national project.

**90. (1)** The Polavaram Irrigation Project is hereby declared to be a national project.

(2) It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the regulation and development of the Polavaram Irrigation Project for the purposes of irrigation.

(3) The consent for Polavaram Irrigation Project shall be deemed to have been given by the successor State of Telangana.

(4) The Central Government shall execute the project and obtain all requisite clearances including environmental, forests, and rehabilitation and resettlement norms.

Arrangements on Tungabhadra Board.

**91. (1)** The Governments of the successor States of Andhra Pradesh and Telangana shall replace the existing State of Andhra Pradesh on the Tungabhadra Board.

(2) The Tungabhadra Board shall continue to monitor the release of water to High Level Canal, Low Level Canal and Rajolibanda Diversion Scheme.

#### PART X

##### INFRASTRUCTURE AND SPECIAL ECONOMIC MEASURES

Successor States to follow principles, guidelines, etc., issued by Central Government.

**92.** The principles, guidelines, directions and orders issued by the Central Government, on and from the appointed day, on matters relating to coal, oil and natural gas, and power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule shall be implemented by the successor States.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1148] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ज्येष्ठ 7, 1936  
No.1148] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2014

**का.आ. 1391(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 85 की उप-धारा (1), उप-धारा (4) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा नदी पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड का गठन करती है, जो निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

- |     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| (क) | केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से भारत सरकार के अपर सचिव स्तर का कोई अधिकारी   | — अध्यक्ष                 |
| (ख) | उत्तरवर्ती राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा प्रत्येक से नामनिर्दिष्ट दो सदस्य, जिसमें एक तकनीकी सदस्य जो मुख्य अभियंता के रैंक से अन्यून नहीं होगा और अन्य प्रशासनिक सदस्य होगा, जो संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे | — सदस्य                   |
| (ग) | केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से एक विशेषज्ञ   | — सदस्य                   |
| (घ) | केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से एक अधिकारी, जो मुख्य अभियंता से अन्यून नहीं होगा   | — सदस्य सचिव (पूर्णकालिक) |
| 2.  | कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद होगा।  |                           |

[फा.सं. 1/1/2014—एसपीआर]

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2014

**S.O. 1391(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (4) and (5) of Section 85 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the Central Government hereby constitutes the Krishna River Management Board for the administration, regulation, maintenance and operation of such projects on Krishna river, as may be notified by the Central Government from time to time, consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

- |     |   |   |                  |
|-----|---|---|------------------|
| (1) | An officer of the level of Additional Secretary to the Government of India from the Central Water Engineering (Group 'A') Service   | - | Chairperson      |
| (2) | Two members, to be nominated by each of the successor States of Telangana and Andhra Pradesh, of which one shall be the technical member not below the rank of Chief Engineer and the other administrative member to represent the concerned States | - | Members          |
| (3) | One expert from the Central Power Engineering (Group 'A') Service   | - | Members          |
| (4) | An Officer not below the rank of Chief Engineer from the Central Water Engineering (Group 'A') Service  | - | Member Secretary |
| 2.  | The headquarters of the Krishna River Management Board shall be at Hyderabad.   |   |                  |

[F. No.1/1/2014-SPR]

URVILLA KHATI, Jt. Secy.

**THE ELEVENTH SCHEDULE**  
**[See section 85(8)(e)]**

*Principles governing the functioning of the River Management Boards*

1. The operation protocol notified by the Ministry of Water Resources with respect to water resources arrived at based on appropriate dependability criteria after the adjudication by the Krishna Water Disputes Tribunal shall be binding on both the successor States.
2. In the event of conflicting demand of water for irrigation and power, the requirement of water for irrigation shall take precedence.
3. In the event of conflicting demand of water for irrigation and drinking water, the requirement of water for drinking water purpose shall take precedence.
4. The allocations made by the River Water Tribunals with regard to various projects on Godavari and Krishna Rivers or for the regions of the existing State of Andhra Pradesh, in respect of assured water shall remain the same.
5. Allocations, if any, to be made on excess flows by any Tribunal in future shall be binding on both the State of Telangana and the Successor State of Andhra Pradesh.
6. While the successor State Governments shall be responsible for managing natural calamities, the Boards shall advise the two State Governments on the management of disaster or drought or flood in the rivers of Krishna and Godavari, particularly in reference to the release of water for the management and mitigation of the natural calamities. The Boards shall have the full authority to get their orders implemented by the two successor State Governments promptly and effectively in respect of operation of the head works of the dams, reservoirs or head works of canals and works appurtenant thereto including the hydel power projects, as notified by the Central Government, on Krishna and Godavari Rivers.
7. No new projects based on water resources arrived at based on appropriate dependability criteria on Godavari or Krishna rivers can be taken up by the State of Telangana or the State of Andhra Pradesh without obtaining sanction from the Apex Council on River water resources. All such proposals shall be first appraised and technically cleared by the respective Board, before sanction by the said Apex Council.

8. Execution of ongoing projects and future new projects on Godavari and Krishna rivers shall be the responsibility of the State Government concerned where the project is located.
9. In case of non-implementation of the decision by either of the States, the defaulting State shall bear the responsibility and shall face financial and other penalties imposed by the Central Government.
10. The following irrigation projects which are under construction shall be completed as per the plan notified by the existing State of Andhra Pradesh and the water sharing arrangement shall continue as such :-

- (i) HandriNiva
- (ii) Telugu Ganga
- (iii) GaleruNagiri
- (iv) Venegondu
- (v) Kalvakurthi
- (vi) Nettempadu

File No.R-12011/7/2016-Pen.Riv.

F. No. R-12011/7/2016-Pen.Riv.  
Government of India  
Ministry of Water Resources,  
River Development and Ganga Rejuvenation

\*\*\*\*

353, Krishi Bhawan, New Delhi  
Dated the 5<sup>th</sup> October, 2018

**ORDER**

**Subject: Constitution of Committee to ensure supply of Krishna water to augment drinking water supply to Chennai city- reg.**

In partial modification of this Ministry's Order of even number dated 07.09.2018, the Committee to ensure supply of Krishna water to augment drinking water supply to Chennai City is hereby re-constituted with following composition:-

- |  |                    |
|--|--------------------|
| i. Chairman, KRMB                                  | - Chairperson      |
| ii. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Maharashtra    | - Member           |
| iii. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Karnataka     | - Member           |
| iv. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Tamil Nadu     | - Member           |
| v. Engineer-in-Chief, I & CAD, Govt of Telangana   | - Member           |
| vi. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Andhra Pradesh | - Member           |
| vii. Chief Engineer, IMO, CWC                      | - Member           |
| viii. Member Secretary, KRMB                       | - Member-Secretary |

2. Terms of Reference of the Committee, as earlier, are the following:-

- i. To evolve mechanism for accounting:
  - a. the flows to be supplied by the States of Maharashtra and Karnataka as per their shares: and
  - b. the flows to be supplied by the States of Telangana and Andhra Pradesh as per their shares to Chennai city water supply as per the interstate agreements so as to realize the agreed quantities of water at Andhra Pradesh - Tamil Nadu border.
- ii. To ensure drinking water supply of water to Chennai city as per the relevant interstate agreements.
- iii. The committee shall meet at least twice in a year in the months of June and December to ensure supply of 8TMC of water during July to October and 4 TMC of water during January to April to Chennai city.
- iv. The venue of the meeting shall be decided by the Chairperson of the Committee from time to time.

  
(A.C. MALLICK)

Under Secretary to the Govt. of India  
Email: uspenriv-mowr@gov.in / ☎ 011-23383059

To

1. Chairman, Krishna River Management Board
2. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Maharashtra

File No.R-12011/7/2016-Pen.Riv.

3. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Karnataka
4. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Tamil Nadu
5. Engineer-in-Chief, I & CAD, Govt of Telangana
6. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Andhra Pradesh
7. Chief Engineer, IMO, CWC
8. Member-Secretary, KRMB

Copy to: Joint Secretary, Inter State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, Vigyan Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi.

Copy for information to :

1. PS to Minister (WR, RD & GR)
2. PS to Secretary (WR, RD & GR)
3. PS to Additional Secretary (WR, RD & GR)



(A.C. MALLICK)

Under Secretary to the Govt. of India  
Email: uspenriv-mowr@gov.in / ☎ 011-23383059

**अनुलग्नक – V**

**कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा जल विनियमन से संबंधित मामलों की चर्चा करने के लिए 18 व 19 जून, 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति।**

**कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा जल विनियमन से संबंधित मामलों के बारे में चर्चा करने के लिए 18 व 19 जून, 2015 को आयोजित बैठक की चर्चा का संक्षिप्त रिकॉर्ड।**

1. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा पानी के उपयोग के नियमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 और 19 जून, 2015 को अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार तथा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।
2. हिस्सेदारों का स्वागत करते हुए, अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
3. आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने जल के नियमन के उद्देश्य से कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं को तत्काल अधिसूचित करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी हवाला दिया कि वर्तमान में बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना राज्य के प्रतिनिधि ने कहा कि परियोजनाओं की अधिसूचना और जल के नियमन के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले यह आवश्यक है कि जल विनियमन के व्यापक सिद्धांतों और एक उपयुक्त कार्यान्वयन तंत्र पर काम किया जाए। इस संबंध में, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि के डब्ल्यू डी टी-1 अधिनिर्णय के अनुसार तत्कालीन आंध्रप्रदेश राज्य को विभिन्न परियोजनाओं में सामूहिक उपयोग के लिए 811 TMC आवंटित किया गया है। हालांकि, तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लिए गए व्यवस्था / विभिन्न निर्णयों के द्वारा की गयी संशोधित आवंटन से दोनों राज्यों को आंध्र प्रदेश में 512 टीएमसी और तेलंगाना में 299 टीएमसी दिया गया।
4. आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि ने विरोध किया कि तेलंगाना का हिस्सा केवल 279 टीएमसी है और कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण के पूरा होने के बाद ही उन्हें भीमा लिफ्ट परियोजना के लिए अतिरिक्त 20 टीएमसी उपलब्ध होगा। तेलंगाना के प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि KWDI-II के समक्ष तत्कालीन आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत संशोधित आवंटन विवरण को दोनों राज्यों द्वारा पालन किया जाना है।

5. बैठक में, यह सहमति हुई कि उपयुक्त मंचों के समक्ष उठाए गए उठायी जानेवाले अधिकारों के बारे में दोनों राज्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न होते हुए दिनांक 18-10-2013 (अनुलग्नक के रूप में संलग्न) बनायी गयी दोनों राज्यों के भागों को आंकड़े में दर्शाई गई परियोजनाओं की सूची को केवल वर्तमान वर्ष की कार्य व्यवस्था के रूप में अनुपालन किया जाए।
6. दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की कि वे अपने हिस्से का जल जहां भी वे तय करते हैं, उस स्थान पर पानी की उपलब्धता के अधीन और दूसरे राज्य के अधिकारों को प्रभावित किए बिना का उपयोग कर सकते हैं।
7. तत्पश्चात, परियोजना से संबंधित मामलों की चर्चा हुयी तथा केवल अस्थायी तौर पर जल वर्ष 2015-2016 के लिए निम्नलिखित कार्य व्यवस्थाओं को उपाय के रूप में सहमति दी गई।

### **नागार्जुन सागर परियोजना**

8. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति बनी कि इस परियोजना से दोनों राज्यों का जल हिस्सा अनुलग्नक के अनुसार होगा। बायीं तट नहर के जल नियंत्रण करते समय वर्तमान प्रचलन के अनुसार केआरएमबी आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्य दोनों की आवश्यकताओं पर विधिवत विचार करेगा।
9. आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची XI के अनुसार यह सहमति हुई कि दोनों राज्यों की मांगों पर विचार करते समय जुड़वां शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकताओं को उचित प्राथमिकता दी जाएगी।

### **कृष्णा डेल्टा प्रणाली**

10. अधिकरण अधिनिर्णय के अनुसार कृष्णा डेल्टा परियोजना, यानी प्रकाशम बैराज, विजयवाडा के लिए 181.2 टीएमसी जल आवंटित किया गया है। हालांकि संलग्न अनुलग्नक के अनुसार कृष्णा डेल्टा का हिस्सा 151.2 टीएमसी है।
11. कृष्णा डेल्टा के जल की जरूरतों को एनएसपी द्वारा पूरक मध्यवर्ती योगदान से पूरा किया जाता है। जहाँ तक पालेरू, मुन्नेरू और मूसी द्वारा नागार्जुन सागर की उपयुक्त निचली धारा जल उपज की मामले में, आंध्रप्रदेश सरकार ने कहा कि वह केवल 20 टीएमसी है। तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधि के अनुसार यह उपज 101.2 टीएमसी है। कृष्णा डेल्टा को रिलीज का निर्धारण करते समय कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा मध्यस्थ आवाहन से वास्तविक उपयोगी जल को ध्यान में रखने की बात पर सहमती हुई।

कृष्णा डेल्टा में नहरों के माध्यम से वास्तविक निर्वहन की मापन तथा मूसी, पलेरू और मुन्नेरू धाराओं से प्रवाह डेटा, पुलिचिंतला में संचयन से धारा आंकड़ों को लेकर कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को ध्यान में रखने हेतु सीडब्ल्यूसी द्वारा नागार्जुन सागर के मध्यस्थ आवाहन निचली धारा से जल की उपयोगी मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा। यह मात्रा कुल आबंटन में से घटाई जाएगी तथा कृष्णा डेल्टा प्रणाली क्षेत्र तथा सिंचाई के लिए नागार्जुन सागर परियोजना से संपूरित किया जाएगा।

12. आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया है कि अगर भीमा परियोजना के लिए 20 टीएमसी जल का उपयोग किया जाना है तो कृष्णा डेल्टा आधुनिकीकरण के खर्च तेलंगाना सरकार द्वारा साझा की जानी चाहिए।। तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधि ने लागत बंटवारे के इस विचार का तीव्र विरोध किया।
13. नागार्जुन सागर परियोजना में नहर प्रणाली की आवश्यकताओं और कृष्णा डेल्टा प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल को विनियमित किया जाएगा।

### **श्रीशैलम जलाशय परियोजना**

14. यह नोट किया गया कि तेलुगु गंगा नहर के माध्यम से चेन्नई जल आपूर्ति (एपी और टीएस शेयर) के लिए 5 टीएमसी की आवश्यकता है और एसआरबीसी के लिए 19 टीएमसी की आवश्यकता है। यह सहमति हुई कि बिजली उत्पादन के लिए रिलीज करते समय नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जलाशय के लिए प्रतिबद्ध उपयोगों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

### **कार्यान्वयन पद्धति**

15. दोनों राज्यों के मुख्य अभियंता और केआरएमबी के सदस्य सचिव युक्त समिति द्वारा संबंधित परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत गई आवश्यकताओं को तथा जल की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांगपत्रों पर विचार करेगी और सिफारिश करेगी। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय संबंधित राज्य परियोजना प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
16. उपरोक्त समिति अनुसंलाग्रक में दर्शित के.सी.कैनाल, जूराला और आरडीएस के माध्यम से जल की रिहाई का भी नियंत्रण करेगा।
17. यह सहमति हुई कि वर्तमान वर्ष में 811 टी.एम.सी. के आवंटन के बाद उपलब्ध जल की मात्रा को आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा। इसी तरह, 811 टी.एम.सी. से नीचे के घाटे को भी तदनुसार साझा किया जाएगा।

18. वर्तमान वर्ष के लिए सहमती प्राप्त संपूर्ण प्रबंधन दोनों राज्यों के लिए किसी भी मंच पर बिना किसी पक्षपात के होंगे।

सभा को धन्यवाद समर्पण के साथ बैठक समाप्त की गई।

हस्ताक्षरित दि : 19.06.2015  
ए.एन. दास  
प्रधान सचिव, डब्ल्यू.आर.डी.  
आंध्रप्रदेश सरकार

हस्ताक्षरित दि : 19.06.2015  
एस.के.जोशी  
प्रधान सचिव, आई व सी.ए.डी विभाग  
तेलंगाना सरकार

हस्ताक्षरित दि : 19.06.2015  
डॉ. अमरजीत सिंह  
अतिरिक्त सचिव  
जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय

अनुलग्नक V का परिशिष्ट

कृष्णा बेसिन में आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों की परियोजनाएँ

क्र म सं	परियोजना का नाम	बचावत प्रतिवेदन के अनुसार	पुनः आवंटन	क्षेत्रवार आवंटन			कुल
				रायलसीमा	तटीय आन्ध्र	तेलंगाना	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>क्षेत्र में विशिष्ट परियोजनाएँ</b>						
1	कृष्णा डेल्टा	181.20	152.20	-	152.20	-	152.20
2	मुनियेरू परियोजना	3.30	3.30	-	3.30	-	3.30
3	पाखल झील	2.60	2.60	-	-	2.60	2.60
4	वैरा	3.70	3.70	-	-	3.70	3.70
5	पालेर	4.0	4.0	-	-	4.0	4.0
6	दिडी	3.70	3.50	-	-	3.5	3.5
7	कर्नूल – कडपा नहर	39.90	31.90	31.90	-	-	31.90
8	कोयिल सागर	3.90	3.90	-	-	3.90	3.90
9	तुंगभद्रा दायां किनारा निचली सतह नहर	29.50	29.50	29.50	-	-	29.50
10	तुंगभद्रा दायां किनारा उच्चस्तरीय नहर स्टेज- I और II	32.50	32.50	32.50	-	-	32.50
11	राजोलिबंडा दिक्परिवर्तन योजना	15.90	15.90	-	-	15.90	15.90
12	भैरवानितिप्पा	4.90	4.90	4.90	-	-	4.90
13	मूसी	9.40	9.40	-	-	9.40	9.40
14	लंकासागर	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0
15	वैकुंठपुरम पंपिंग योजना	2.60	2.00	-	2.0	-	2.0
16	कोटिपल्लि वागु	2.0	2.0	-	-	2.0	2.0
17	गुंटूर चैनल	4.0	4.0	-	4.0	-	4.0
18	ओकाचेट्टी वागु	1.90	1.90	-	-	1.90	1.90
19	गाजुलदिन्ने	2.0	2.0	2.0	-	-	2.0

20	जूराला बाँध	17.84	17.84	-	-	17.84	17.84
21	सिकंदराबाद और हैदराबाद के जुड़वां शहरों में जलापूर्ति	3.90	5.70	-	-	5.70	5.70
22	लघु सिंचाई	116.26	111.26	12.24	9.87	89.15	111.26
<b>कुल (I)</b>		<b>486.00</b>	<b>445.00</b>	<b>113.04</b>	<b>171.37</b>	<b>160.59</b>	<b>445.00</b>
<b>II आम परियोजनाएँ</b>							
23	नागार्जुन सागर परियोजना	281.00	280.00		174.30	105.70	280.00
24	श्रीशैलम (वाष्पीकरण हानियाँ)	33.00	33.00	11.00	11.00	11.00	33.00
25	चेन्नई शहर जल आपूर्ति		5.00	1.66	1.67	1.67	5.00
<b>कुल (II)</b>		<b>314.00</b>	<b>318.00</b>	<b>12.66</b>	<b>186.97</b>	<b>118.37</b>	<b>318.00</b>
<b>III बचत और वापसी प्रवाह पर आधारित नई परियोजनाएं</b>							
26	श्रीशैलम दाहिनी शाखा नहर		19.00	19.00			19.00
27	पुलिचिंताला परियोजना		9.00		9.00		9.00
28	राजीव (भीम) लिफ्ट योजना (जूराला तट से)		20.00			20.00	20.00
29	वापसी बहाव	11.00					
<b>कुल (III)</b>		<b>11.00</b>	<b>48.00</b>	<b>19.00</b>	<b>9.00</b>	<b>20.00</b>	<b>48.00</b>
<b>कुल (I+II+III)</b>		<b>811.00</b>	<b>811.00</b>	<b>144.70</b>	<b>367.34</b>	<b>298.96</b>	<b>811.00</b>

**नोट:**

1. उपरोक्त विवरण उन परियोजनाओं के स्थान के आधार पर तैयार किया गया है जिनके लिए KWDI-I द्वारा आवंटन किया गया है।
2. हैदराबाद जल आपूर्ति योजना को 3.3 टीएमसी के उपभोग्य उपयोग के साथ शुरू किया गया था जो डिंडी परियोजना से 0.2 टीएमसी, वैकुंठपुरम पीएस से 0.6 टीएमसी, नागार्जुन सागर परियोजना से 1.0 टीएमसी और जुड़वा शहरों को जलापूर्ति के लिए 3.9 टीएमसी में से 1.50 टीएमसी की बचत के साथ किया गया था। (आंध्र प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग G.O.Ms.No.19 दि: 05.02.2003).

3. महबूबनगर जिले में भीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (20 टीएमसी) और पुलिचिंताला परियोजना (वाष्पीकरण हानियों के लिए 9 टीएमसी) को कृष्णा डेल्टा के आधुनिकीकरण द्वारा प्रस्तावित बचत के खिलाफ लिया गया है। (सलाहकार समिति की 64वीं बैठक में सीडब्ल्यूसी का अनुमोदन पत्र संख्या 10/27/96-पीए (एन)/502-550 दिनांक: 16.04.1996)
4. श्रीशैलम दायीं तट नहर को बचवत ट्रिब्यूनल द्वारा आवंटित 11 टीएमसी और बचत के माध्यम से 8 टीएमसी के.सी. नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के कारण के वापसी प्रवाह के साथ लिया गया था। (सीडब्ल्यूसी सलाहकार समिति की 58वीं बैठक द्वारा अनुमोदित पत्र संख्या 16/27/94-पीए (एन) दिनांक: 04.07.1994)।
5. एपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 14.04.1976 के समझौते के अनुसार चेन्नई जल आपूर्ति के लिए एपी सरकार के योगदान के लिए आंध्रप्रदेश को 5 टी.एम.सी पुनः आवंटित किया गया। । यह 5 टीएमसी लघु सिंचाई आवंटन में से तीन क्षेत्रों में समान रूप से दिखाया गया है।
6. श्रीशैलम जलाशय के लिए 33 टीएमसी का वाष्पीकरण नुकसान तीन क्षेत्रों के बीच समान रूप से दिखाया गया है।
7. नागार्जुन सागर परियोजना का आवंटन "नागार्जुन सागर परियोजना, तृतीय संशोधित परियोजना अनुमान 2000" के अनुसार दिखाया गया है और आवंटन के अनुपात में वाष्पीकरण हानि शामिल है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित दि : 18.10.2013

मुख्य अभियंता (ओ एस डी), आई एस व डब्ल्यू आर  
मुख्य अभियंता के लिए (ओ एस डी), आई एस व डब्ल्यू आर

**अनुलग्नक - VI**

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों द्वारा प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं (लघु परियोजनाओं को छोड़कर) से नहर / योजना-वार पानी का आहरण (टीएमसी में) ।

क्र.सं	परियोजना का नाम	आंध्रप्रदेश द्वारा आहरित जल (टीएमसी)	तेलंगाना द्वारा आहरित जल (टीएमसी)	कुल आहरित (टीएमसी)
<b>A</b>	<b>श्रीशैलम परियोजना</b>			
1	महात्मा गाँधी कल्चकुर्ति लिफ्ट सिंचाई योजना		31.566	31.566
2	पोतिरेड्डी पाडु हेड रेगुलेटर	109.694		109.694
3	हन्द्री नीवा सुजल स्रावंधी परियोजना	25.981		25.981
4	मुचुमरी लिफ्ट सिंचाई योजना	1.561		1.561
5	चेन्नई जल आपूर्ति	4.233	2.117	6.350
	<b>कुल</b>	<b>141.469</b>	<b>33.682</b>	<b>175.151</b>
<b>B</b>	<b>नागार्जुन सागर परियोजना</b>			
1	हैदराबाद मेट्रो जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (HMWS & SB)		16.557	16.557
2	एलिमिनेटि माधव रेड्डी परियोजना & बाढ़ प्रवाह नहर		36.287	36.287
3	नागार्जुन सागर बायें नहरें	23.406	114.438	137.844
4	नागार्जुन सागर दाहिनी नहरें	166.151		166.151
5	कृष्णा डेल्टा प्रणाली	172.235		172.235
6	गुट्टर चैनल	3.365		3.365
	<b>कुल</b>	<b>365.157</b>	<b>167.281</b>	<b>532.438</b>
<b>C</b>	<b>तुंगभद्रा परियोजना</b>			
1	तुंगा भद्रा परियोजना उच्च स्तरीय नहर	32.500		32.500
2	तुंगा भद्रा परियोजना निम्न स्तरीय नहर	23.352		23.352
3	के सी नहर	52.729		52.729
4	आर डी एस		7.288	7.288
	<b>कुल</b>	<b>108.581</b>	<b>7.288</b>	<b>115.869</b>
<b>डी</b>	<b>जूराला परियोजना</b>			
1	जूराला परियोजना		28.004	28.004
2	नेट्टेमपाडु एल आई एस		8.854	8.854
3	भीमा एल आई एस		11.573	11.573
4	कोइल सागर एल आई एस		1.890	1.890
	<b>कुल</b>	<b>0.000</b>	<b>50.321</b>	<b>50.321</b>

ई	मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ			
1	मूसी		0.431	0.431
2	पखाला झील		1.240	1.240
3	वेरा		2.000	2.000
4	लंकासागर		0.008	0.008
5	दिडी		2.300	2.300
6	पालेरू		0.500	0.500
7	कोटिपल्लि वागु		0.000	0.000
8	मुनियेरु	3.791		3.791
9	गाजुलादित्रे	2.029		2.029
10	पुलिचिंताला परियोजना	0.000		0.000
11	भैरवानितिप्पा	0.814		0.814
12	सुंकेसुला			0.000
	<b>कुल</b>	<b>6.634</b>	<b>6.479</b>	<b>13.113</b>
<b>एफ़</b>	<b>कुल योग I (A+B+C+D+E)</b>	<b>621.841</b>	<b>265.051</b>	<b>886.892</b>

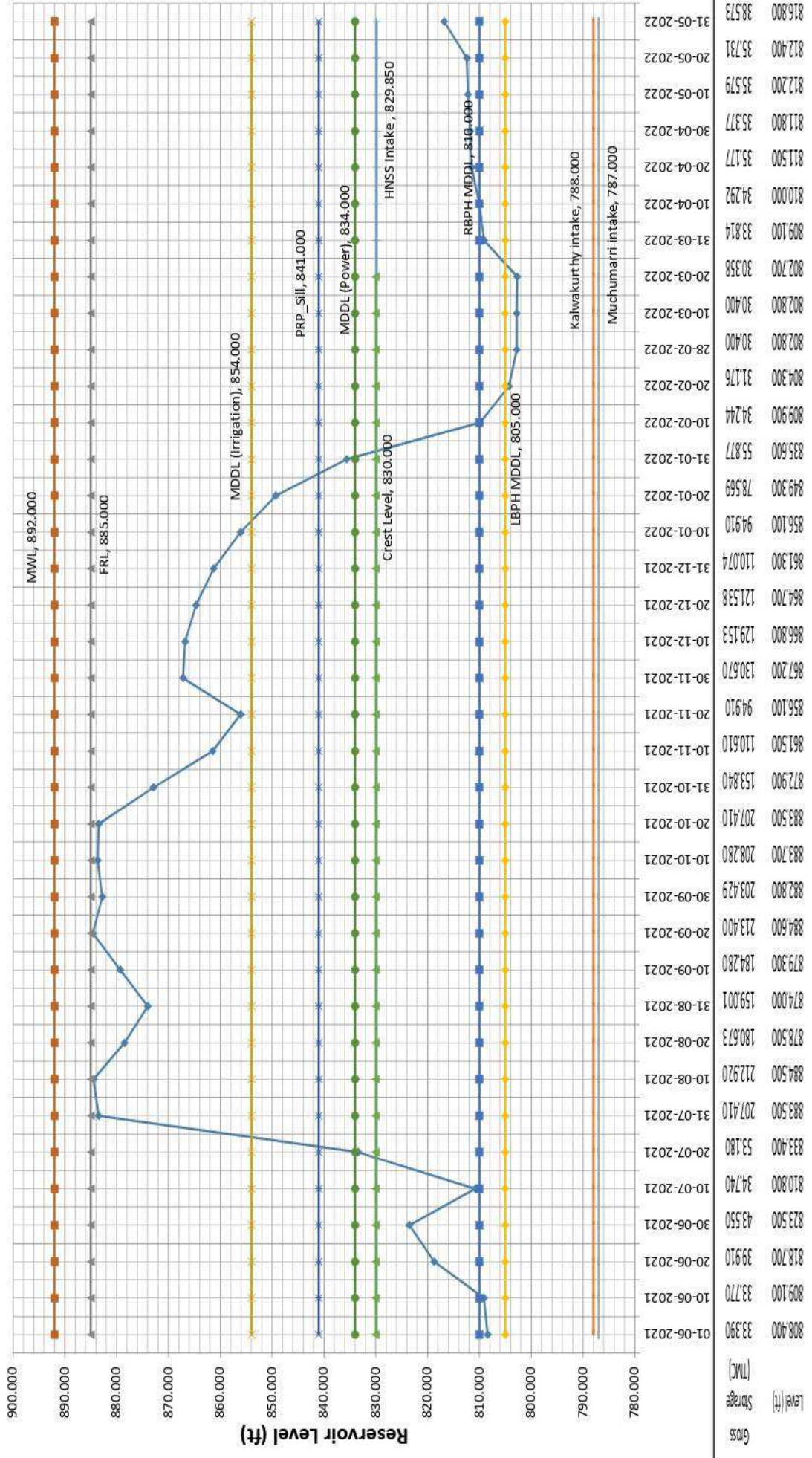
अनुलग्नक- VII

आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण

क्रम. सं.	हाईड्रो पावर परियोजना	सामर्थ्य (मेगावाट)	ऍफ़ आर एल	एमडीडीएल	बहाव	पंप पद्धति में प्रचालन की सुविधा	राज्य
1	प्रियदर्शिनी जूराला	6 x 39	+318.516 मी	+314.86 मी	--	--	तेलंगाना
2	निचली जूराला	6 x 40	+299.000 मी	+294.00 मी	--	--	तेलंगाना
3	श्रीशैलम दायीं तट	7x110	+269.748 मी	+254.200 मी	--	--	आंध्रप्रदेश
4	श्रीशैलम बायीं तट	6 x 150	+269.748 मी	+243.84 मी	--	पंप पद्धति प्रचालन के लिए सभी टर्बाइन प्रतिवर्ती प्रकार के हैं।	तेलंगाना
5	नागार्जुन सागर बांध	1 x 110 + 7 x100.8	+179.832 मी	+154.230 मी कन्वेंशनल के लिए और +150.880 मी रिवेर्सिबल यूनिट के लिए	4700 कन्वेंशनल /4300 प्रतिवर्ती प्रति यूनिट के लिए	पंप पद्धति प्रचालन के लिए 7 x 100.80 मेगावाट प्रतिवर्ती प्रकार का हैं।	तेलंगाना
6	नागार्जुन सागर दायीं नहर	3 x 30.6	+179.832 मी	+161.544 मी	5000 क्यूसेक प्रति यूनिट	--	आंध्रप्रदेश
7	नागार्जुन सागर बाईं नहर	2 x 30.6	+179.832 मी	+167.030 मी	--	--	तेलंगाना
8	नागार्जुन सागर टेल पांड	2 x25	+75.50 मी	+74.0मी	--	--	आंध्रप्रदेश
9	पुलिचिंतला	4 x 30	+53.34 मी	+42.67 मी	--	--	तेलंगाना

PLATE - I

Srisaillam Reservoir 2021-22



10 Daily

PLATE - II

Nagarjuna Sagar Project 2021-22

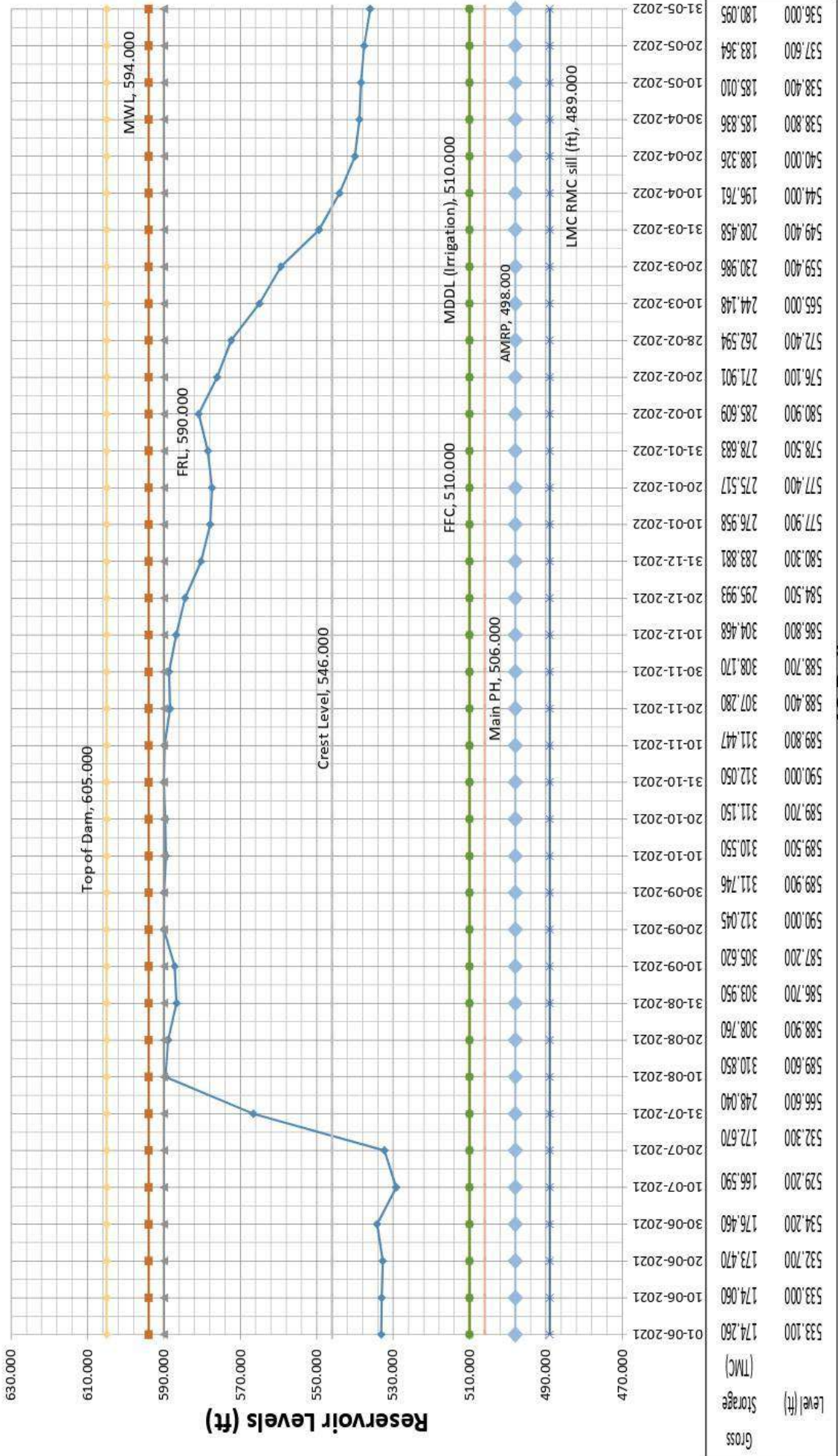


PLATE - III

Comparison of Srisaillam LPH and RPH for the water Year 2021-22

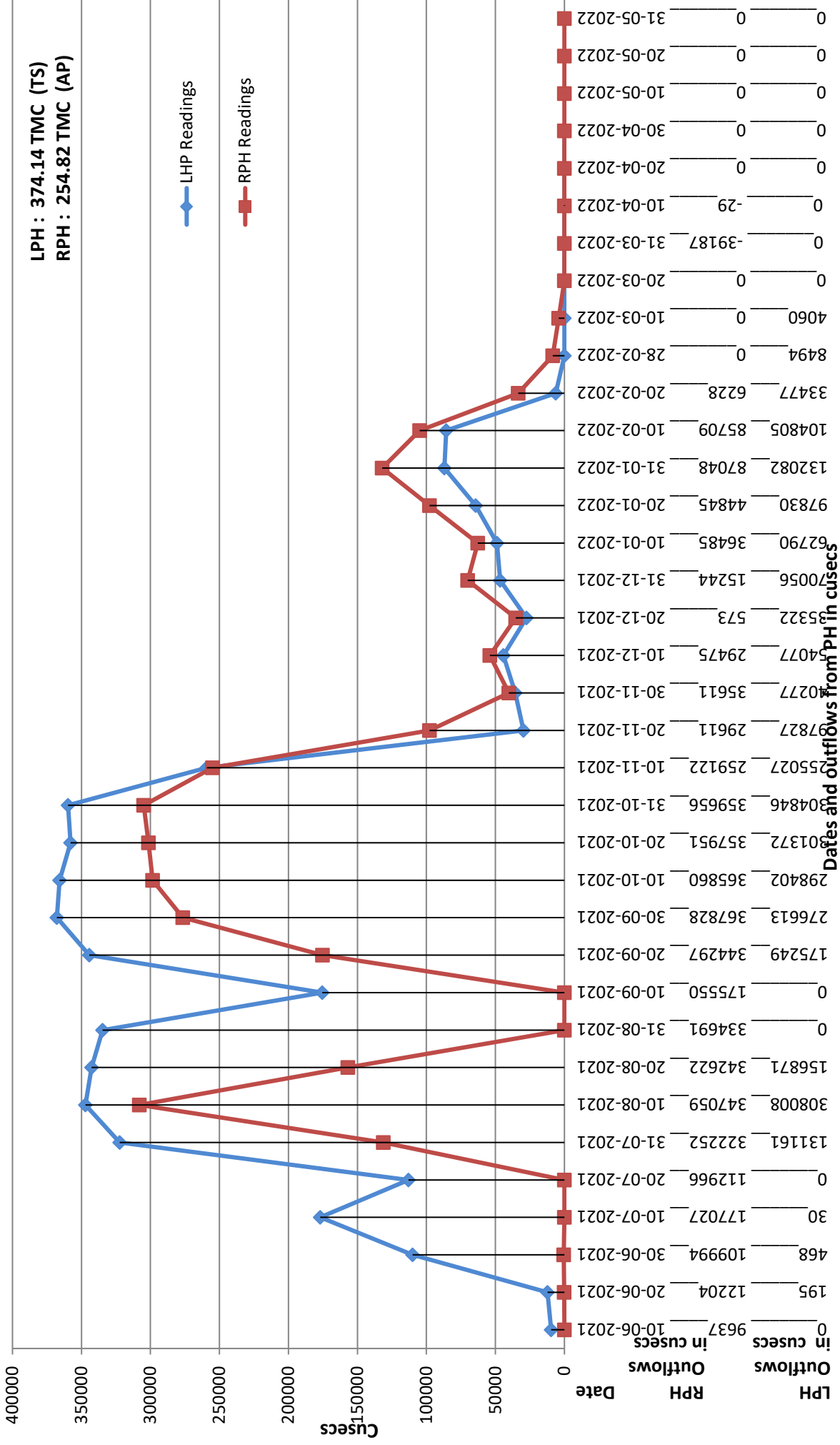
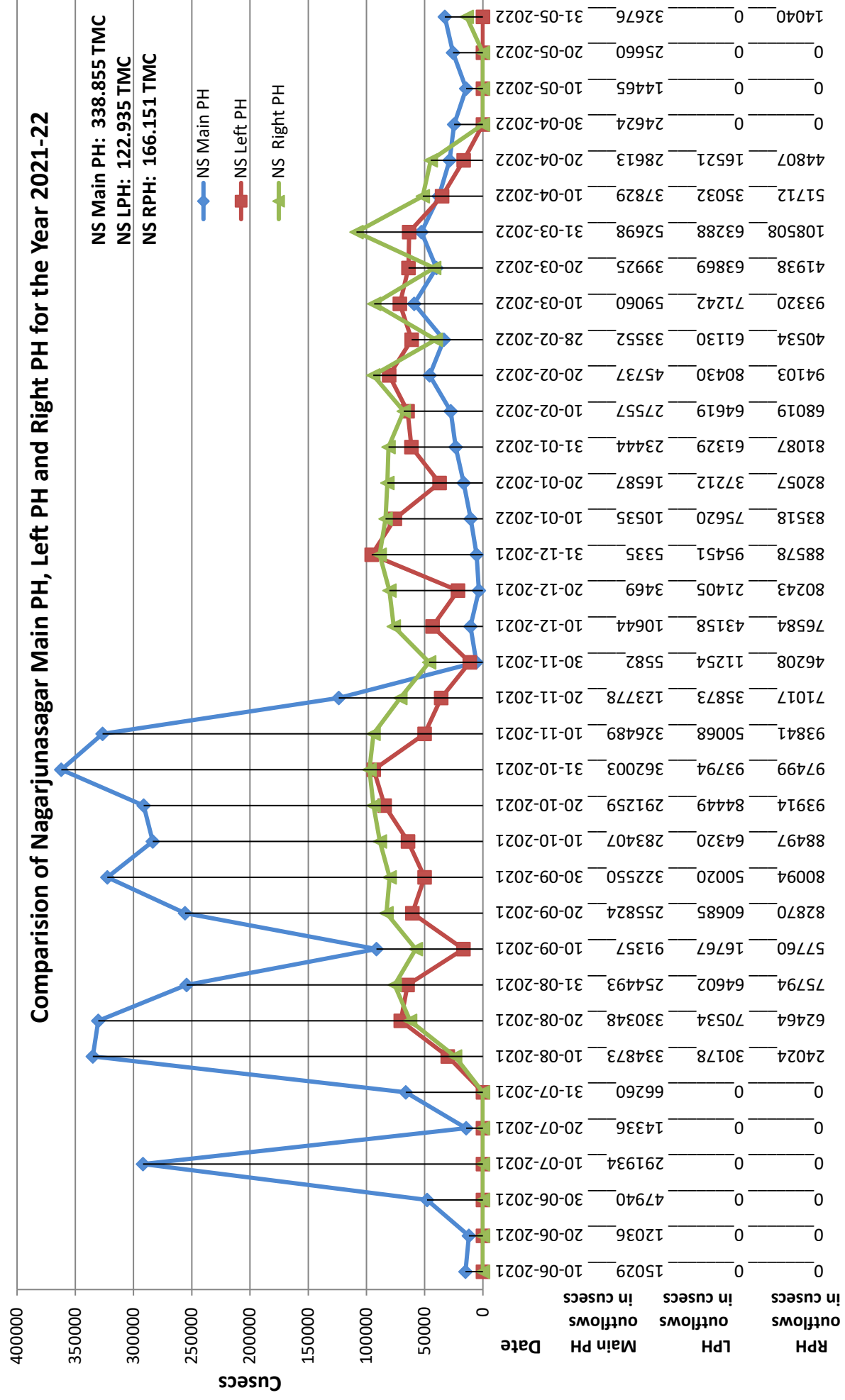


PLATE - IV



Dates and outflows from PH in cusecs





प्रकाशम बैराज

## कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

5 वीं मंजिल, जल सौधा, इरम-मंजिल,  
हैदराबाद – 500 082

दूरभाष: 040-23301858; फ़ैक्स: 040-23301655

ई-मेल: [krmb.hyd@gmail.com](mailto:krmb.hyd@gmail.com)

**Website: <https://krmb.gov.in>**